

बंग के रंग में भंगा

महेश बेंक चुनाव में महिलाओं को लेकर सारे कथासों के विपरीत संस्थापक पैनल को नारी शक्ति ने भी भारी समर्थन दिया। महिला कैटेगरी से संस्थापक की दोनों प्रत्याशी अलका झंवर (6782) व कविता तोष्णीवाल (7404) ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी रजनी राठी (5760) व तारा मालू (5382) को बड़े अंतर से हराया। देर रात करीब 2 बजे इनके वोटों की गिनती पूरी हुई। सभी नतीजों की आधिकारिक/औपचारिक घोषणा 16 को दिल्ली से होगी। खुशियां मनाने के लिए अब 16 तक इंतजार करना होगा।

3 जुलाई 2025 को कोआपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी (सीईए), नई दिल्ली द्वारा जारी चुनावी शेड्यूल के 'विशेष' निशानिदेशानुसार सामान्य श्रेणी के 12, महिला वर्ग के 2 व एससी/एसटी के 1 पद

(कुल 15) के लिए मतदान 7 दिसंबर 2025 और मतगणना 8 दिसंबर को संपन्न हुई। एससी/एसटी पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं था। 9 दिसंबर को 19एम फार्म में मतगणना के नतीजों की सम्पूर्ण जानकारी चुनाव अधिकारी द्वारा सीईए, नई दिल्ली को सिफारिश के साथ अप्रुवल के लिए भेजी गई।

नव निर्वाचित बोर्ड आफ डायरेक्टर की सूची को मंजूरी मिलने के बाद 16 दिसंबर को जिलाधीश कार्यालय, बैंक के बंगरा हिल्स स्थित मुख्यालय व आधिकारिक वेबसाइट पर विजेताओं की सूची जारी की जाएगी। तत्पश्चात 18 दिसंबर को चेयरमैन व वाईस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 9 बजे नामांकन, 1 बजे छंटनी, 3 बजे तक नाम वापसी और



माँ भगवती की कृपा...

फिर अंतिम योग्य उम्मीदवारों की सूची। यदि जरूरत पड़ी तो 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे मतदान होगा। ज्ञातव्य है कि 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से एक्जीक्यूटिव ग्राउंड स्थित कमला नेहरू पालटेक्निक कालेज परिसर में कड़े पुलिस बंदोबस्त में मतगणना का काम शुरू हुआ था।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बैंक की शाखाओं में हुए मतदान की पेटियाँ यहाँ लाई गई थी। भीलवाड़ा से रात करीब 8 बजे विमान से अंतिम बैलेट बाक्स पहुंचा। सवेरे तीस टेबलों पर 9 राउंड में गिनती का काम चालू हुआ। प्रत्येक राउंड में 1500 वोट गिने गये। छन-छन कर बाहर आ रही उपरोक्त अपुष्ट खबरों के अनुसार, कुछेक मतदाता घर से ही मत-पत्र लेकर आए और स्याही का

निशान लगाकर मत पेटी में डाल दिया। दरअसल प्रचार के दौरान समझाने के लिए ऐसे डम्मी मत-पत्र बांटे गये थे।

कुछ मत-पत्र ऐसे भी पाये गये, जिसमें मतदाता ने 12 में से केवल एक को ही वोट दिया। इस तरह सिंगल वोट वाले तीन मत-पत्र पाये गये। मतगणना के दौरान मतदान केंद्र में केवल उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को ही अनुमति थी।

इस बार मीडिया को भी कोई पास नहीं दिया गया, जिसे लेकर मीडिया ने गहरी नाराजगी दिखाई। हालांकि बाद में मतगणना केंद्र कालेज भवन के नीचे अनुमति दी गई।

शुभ लाभ ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक द्वारा करीब 5,000 लोगों को यथासंभव समय समय पर ताजा अपडेट दिया। जिसकी काफी प्रशंसा हुई।

वंदे मातरम् पर तुष्टिकरण नहीं होता तो देश का बंटवारा नहीं होता : शाह

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में कहा कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति के तहत वंदे मातरम् को दो हिस्सों में नहीं बांटा होता तो देश का बंटवारा भी नहीं होता।



श्री शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल के मौके पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर शुरू से ही वंदे मातरम् का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् के 50 साल पूरे हुए तो वंदे मातरम् को दो हिस्सों में बांटा गया। वहीं से तुष्टिकरण की शुरुआत हुई और देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा, मेरा और बहुत से लोगों का मानना है कि तुष्टिकरण नहीं होता तो देश का बंटवारा नहीं होता।

कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर वंदे मातरम् के विरोध का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में संसद में वंदे मातरम् का गान बंद कर दिया

गया था, बावजूद इसके कि संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् के 100 साल हुए तो देश में आपातकाल लगा था। गृह मंत्री ने कहा, कल भी जब वंदे मातरम् के 150 साल के मौके पर लोकसभा में चर्चा हुई तो कांग्रेस की एक नेत्री ने कहा - अभी इस समय वंदे मातरम् की चर्चा की जरूरत नहीं है। इस पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने आपत्ति की और उनसे सदन को पूरी बात बताने की मांग की।

श्री शाह ने कहा कि जिस गीत को

महात्मा गांधी ने देश की आत्मा से जुड़ा गीत बताया था उसका टुकड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1992 में जब लोकसभा में दोबारा वंदे मातरम् का गान शुरू हुआ तो मईडियाफ गुट के कई सदस्यों ने उसे गाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब वंदे मातरम् के गायन का समय होता है तो कांग्रेस के कई सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ वंदे मातरम् का गायन करते हैं।

इस पर विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि वह प्रमाण दें कि कौन वंदे मातरम् के गायन के समय खड़ा नहीं होता। वंदे मातरम् के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि उस जमाने में इस नारे ने देश की आजादी में योगदान दिया था, अब अमृतकाल में यह देश को विकसित और महान बनाने का काम करेगा।

तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का समापन 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य वाला विजन-2047 डॉक्यूमेंट जारी

हैदराबाद, 09 दिसंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

दो दिवसीय तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का समापन मंगलवार शाम को भारत फ्यूचर सिटी में मतेलंगाना राइजिंग-2047 विजन डॉक्यूमेंट को जारी करने के साथ हुआ।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि नया विजन चार करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य हर नागरिक को स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि इस ब्लूप्रिंट में 2034 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक 3 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के साथ-साथ अब प्राथमिकताएँ शिक्षा, सिंचाई और संचार हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबी में बड़े होने के उनके अपने अनुभव ने गरीबों को कल्याण



पहुँचाने और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स, स्किल्स यूनिवर्सिटी और प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने के उनके संकल्प को मजबूत किया है।

उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने कहा कि विजन-2047 डॉक्यूमेंट व्यापक जनता के परामर्श, फील्ड विजिट और विशेषज्ञ

इनपुट के माध्यम से सह-निर्मित किया गया है, जिससे यह तेलंगाना के लोगों के स्वामित्व वाला एक साझा रोडमैप बन गया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट को आकार देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आईएसबी डीन मदन पिल्लुटला और कई हितधारकों को धन्यवाद दिया, और तेलंगाना के गठन में सोनिया गांधी की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने तेलंगाना के तेजी से उच्च-मध्यम-आय की स्थिति तक बढ़ने पर प्रकाश डाला और कहा कि अब राज्य को मध्यम-आय के जालफसे बचने के लिए नवाचार, उत्पादकता और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इसे विश्व स्तर पर देखे गए सबसे महत्वाकांक्षी और जन-केंद्रित योजनाओं में से एक बताया।

►10पर

इंडिगो को मिली यात्रियों को रुलाने की सजा

10 प्रतिशत उड़ानें कम करने का आदेश

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

सरकार ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने वाली एयरलाइन इंडिगो पर कार्रवाई करते हुए उसे उड़ानों की संख्या 10 प्रतिशत कम करने का आदेश दिया है।

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने मंगलवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एलबर्स को तलब किया था। बैठक में नागर विमानन महानिदेशक फैज अहमद किदवाई भी मौजूद थे।

बैठक के बाद श्री नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मंत्रालय की राय में इंडिगो की कुल रूटों में कटौती अनिवार्य है, ताकि एयरलाइन के परिचालन में स्थिरता आ सके और कम उड़ानें रद्द हों। दस प्रतिशत की कटौती का आदेश दे दिया गया है। इस आदेश का पालन करते हुए इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी।

इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आठ दिसंबर को एक नोटिस जारी कर इंडिगो से विंटर शेड्यूल



में घोषित उसकी उड़ानों की संख्या में पांच प्रतिशत की कटौती का निर्देश दिया था। मंत्रालय के आदेश के बाद डीजीसीए ने अपने आदेश में संशोधन किया है, जिसमें उड़ानों में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया गया है।

श्री नायडू ने अपने पोस्ट में

कहा है कि चालक दल के सदस्यों की ड्यूटी से संबंधित इंडिगो के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण पिछले सप्ताह बड़ी संख्या में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जांच और अन्य जरूरी कार्यवाही जारी है। इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ एक और बैठक हुई। आज फिर

इंडिगो के सीईओ पीटर एलबर्स को अपडेट देने के लिए मंत्रालय में तलब किया गया था।

डीजीसीए के आदेश के अनुसार, उड़ानों की संख्या में कटौती विशेष रूप से उच्च मांग वाले और ऐसे सेक्टरों पर की जायेगी जहां उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। एक मात्र उड़ान इंडिगो की है, वहां कटौती नहीं की जायेगी, एयरलाइंस को 10 दिसंबर शाम पांच बजे तक संशोधित शिड्यूल सौंपने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो ने सितंबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में हर सप्ताह 15,014 उड़ानों की

घोषणा की थी। दस प्रतिशत कटौती का मतलब है कि उसे हर सप्ताह 1,500 उड़ानें कम करनी होंगी।

नियामक ने बताया कि शिड्यूल के मुताबिक इंडिगो को नवंबर में 64,346 उड़ानों का संचालन करना था जबकि उसने मात्र 59,438 उड़ानों का संचालन किया और 951 उड़ानें रद्द रहीं। इसके अलावा उसके बेड़े में मौजूद 403 विमानों में से अक्टूबर में एयरलाइंस ने मात्र 339 विमानों और नवंबर में 344 विमानों का परिचालन किया। ►10पर

सामाजिक योजनाओं में देरी पर संसदीय पैनल सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट, लगाई फटकार

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

संसदीय समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति, ओबीसी और अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में लगातार देरी, धन के सही उपयोग न होना और केंद्र-राज्य समन्वय की कमजोरियों ने इन कार्यक्रमों के प्रभाव को कम कर दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि ऐसी ढिलाई उन समुदायों के विकास के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकती है, जिनके लिए ये योजनाएँ बनाई गई हैं।

लोकसभा में पेश की गई अपनी 14वीं रिपोर्ट में समिति ने साफ कहा कि कौशल विकास, प्री कोचिंग, वेंचर कैपिटल सहायता और हाउसिंग निर्माण जैसी बड़ी योजनाएँ फाईलों में अटक पड़ी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बजट तो दिया जाता है, लेकिन प्रक्रियागत देरी और निगरानी की कमजोर व्यवस्था के कारण जमीन पर काम नहीं दिखता। खासतौर पर पीएम-दक्ष योजना में मंत्रालय फरवरी 2024 तक एक रुपये भी खर्च नहीं कर पाया था, जिससे हजारों युवाओं के प्रशिक्षण पर असर पड़ा। ►10पर

व्यवस्था सुधारने के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए: मोदी

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि व्यवस्था सुधारने के नाम पर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिये।

श्री मोदी ने संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की संसदीय दल की बैठक में कहा कि नियम और कानून जरूरी है लेकिन व्यवस्था को सुधारने के नाम पर जनता को असुविधा देना उचित नहीं है। किसी भी हाल में लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी



कानून या नियम में ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब पूरी तरह मरिफार्म एक्सप्रेस

के चरण में है, जहाँ सुधार तेज, स्पष्ट और नागरिक-केंद्रित हैं। उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सकें।

बैठक के बाद श्री संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तीसरी पारी में सुधारों पर जोर दिया है और अब मोदीजी की रिकॉर्ड एक्सप्रेस चल चुकी है और से रूकने वाली नहीं है। सभी हर स्तर पर ►10पर

माइक्रोसॉफ्ट करेगा 1.57 लाख करोड़ का बड़ा निवेश, भारत में बनेगा एआई हब, पीएम मोदी से मिले नडेला का ऐलान

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने मंगलवार को घोषणा की कि वह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे और कौशल निर्माण हेतु 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जो एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। उन्होंने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा की। नडेला ने ट्वीट किया भारत के एआई



अवसर पर प्रेरक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। देश की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट भारत के एआई-प्रधान भविष्य के लिए आवश्यक

बुनियादी ढाँचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद के लिए एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश - 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर - करने की प्रतिबद्धता जता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नडेला की यह मुलाकात इस साल की शुरुआत में उनके उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी अगले दो वर्षों में भारत में क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किलिंग में 3 अब डॉलर का निवेश करेगी, ►10पर

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025
बेंगलूरु

नम्मा बेंगलूरु

3

किसानों ने सुवर्णा सौधा को घेर लिया

कर्नाटक वह राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की: बी.वाई. विजयेंद्र



बेलगावी/शुभ लाभ व्यूरो।
विपक्षी भाजपा ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के किसान विरोधी खेचे की निंदा करते हुए तुरंत मक़ा खरीद और खोलने की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता अ.शोक, विपक्ष परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी, विधायक मुनिरतन, बालचंद्र जाक्रीहोली, शशिकला जोले, सदस्य रविकुमार, नवीन, भारतीशेट्टी, रायता मोर्चा के अध्यक्ष नादहल्ली, पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य, विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष और पदाधिकारी और

अन्य उपस्थित थे। बेलगावी के मालिनी मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में राज्य के विभिन्न हिस्सों से हजारों किसानों ने भाग लिया और राज्य कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मालिनी मैदान से नेशनल हाईवे 4 के जॉरिए सुवर्णा सौधा को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और किसानों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी दाढ़ों और मक्के की प्रदर्शनी लगाई और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हवा तौलिया और पीला रुमाल बांधे

प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया कि राज्य सरकार बेवजह केंद्र सरकार पर उलू बैठा कर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक वह राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जब-जब कांग्रेस सरकारें आई, किसानों की आत्महत्या के मामले आम थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम और डीसीएम अक्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के बजाय कुर्सी की लड़ाई में लगे हुए हैं। राज्य सरकार गधन किसानों की समस्या का समाधान



नहीं कर रही है। किसान सड़कों पर उतर आए, राजमार्गों को अवरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की हत्याएं लगातार जारी हैं, लेकिन सरकार अंधी है और उनकी तरफ देखती भी नहीं है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हर बात केंद्र पर थोप रही है। मक़े के लिए एमएसपी 2,400 रुपये प्रति किंटल है। हालांकि, इसमें क़ायम केंद्र न खोलकर केंद्र पर फोकस किया गया है। सबसे पहले उन्होंने मांग की कि आप क़ायम केंद्र खोलें। परिषद सदस्य सीजी रवि ने कहा कि हम किसी निजी स्वार्थ के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं।

किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं।

कल्याण कर्नाटक और मध्य कर्नाटक में दाल और मक्का न खरीदकर आप किसानों के पेट पर वार कर रहे हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि हम किसान समर्थक सरकार हैं। दूसरी ओर आप उन्हीं किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह किसानों सा न्याय है। मैंने किसानों की तरफ से 30 जिलों में लड़ाई लड़ी है। हमारा आग्रह है कि उन्हें न्याय मिले। अगर आप पैसा दे देते तो क्या किसान राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर देते। यदि केंद्र सरकार की एएसआरपी के अनुसार किसानों को न्याय मिलता तो क्या

यह समस्या उत्पन्न होती। चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल किसानों के पक्ष में हैं या चीनी मिलों के मालिकों के। मक्का क्रय केन्द्र खोलने का मतलब है कि सरकार विधायकों के लिए क्रय केन्द्र खोलने जा रही है। तुंगभद्रा बांध के गेट की मरम्मत हुए डेढ़ साल बीत चुके हैं। इसकी अब तक मरम्मत नहीं हुई है। आप के किसानों का मुद्दा नहीं बल्कि किसान विधायक को किस तरफ खींचा जाए, कुर्सी कैसे सुरक्षित करें वह इसी में व्यस्त हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता नारायण स्वामी ने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है।

डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में वरिष्ठ नागरिक से 80.5 लाख की ठगी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

एक 74 वर्षीय व्यक्ति और उसकी बहन डिजिटल गिफ्टरानी के नवीनतम शिकार बन गए हैं और एक पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) का रूप धारण करने वाले और मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के बहाने बड़ी रकम स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने वाले साइबर जालसाजों के एक गिरोह ने उनसे कुल 80.5 लाख ठग लिए। शनमुगावेलु द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, घटना 30 अक्टूबर, 2025 को सुबह लगभग 9.30 बजे शुरू हुई, जब उन्हें एक व्हाट्सएप कॉल आया और कॉल करने वाले ने दावा किया कि उनका मोबाइल नंबर एक अंतरराष्ट्रीय मनी-लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा था और जांच की गिरानी एक डीएसजी द्वारा की जा रही थी। जालसाज ने आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज साझा किए और पीड़ित को आश्चर्य किया कि उसके बैंक खाते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच के दायरे में हैं। उनसे कहा गया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक वित्तीय विवरण को तुरंत सत्यापित किया जाना चाहिए। दावे पर विश्वास करते हुए पीड़ित ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया, जिसमें उसके 30 लाख की डाकघर साविधि जमा का विवरण भी शामिल था। इसके बाद घोटालेबाजों ने कई अ

हाइड्रासैफे नंबरों के माध्यम से
उससे संपर्क किया और उन्हें
सत्यापन के लिए जमा राशि
स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
31 अक्टूबर, 2025 को, पीडित
ने 35 लाख ट्रांसफर किए, उसके
बाद अपने बैंक खाते को खत्म
करने के बाद एक और ट्रांसफर
किया। उनकी बहन शशिकलावती
की बचत जमा राशि को भी
भुनाया गया और जमा किया
गया। आरोपियों ने दोनों को
धमकी दी कि वे बाहर न निकलें
और घर को अंदर से बंद कर लें
और जांच पूरी होने तक किसी से
बात न करें और उनका सहयोग न
करें। आरोपियों ने भाई-बहन को
घर से बाहर निकलने पर गिरफ्तार
करने की धमकी भी दी। डरे हुए
दोनों ने निर्देशों का पालन किया
और कई लेनदेन में पैसे ट्रांसफर
कर दिए। बाद में, एक अन्य कॉल
करने वाले ने उसे आश्वस्त किया
कि अधिकारी उसके घर आएंगे
और उसे नकदी तैयार रखनी
होगी। जब कोई नहीं आया तो
उसे संदेह हुआ लेकिन उसने पहले
अपनी संवेदनशील जानकारी
साझा कर दी थी। 29 नवंबर को
पीडितों को आरोपियों का दोबारा
फोन आया और उन्होंने आगे की
प्रक्रिया के लिए नजदीकी पुलिस
स्टेशन जाने को कहा। घोटाले
तब सामने आया जब शनमुगावेलु
अपडेट लेने के लिए स्टेशन गए
और उन्हें पता चला कि उनके
साथ धोखाधड़ी हुई है।

चार मनोनीत सदस्यों को परिषद में नियुक्त किया

परिषद् में कांग्रेस को बहुमत, सभापति बदलने की फिराक में सरकार?



वेगलूर/शुभ लाभ व्यूरो।
कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक बयान दिया है। उन्होंने सोमवार शाम को एक बार फिर से कहा कि वह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से बार-बार कह रहे हैं कि वह और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री परिवर्तन के बारे में हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, वह उसे मानेंगे। सिद्धरामैया ने अपने बेटे और कांग्रेस एमएलसी यतींद्र सिद्धरामैया के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा, उसका पालन करेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि अभी नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है।

इसमें कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। वहीं सिद्धार्थैया को जनवरी में दिल्ली आने के लिए कहे जाने के सवाल पर, यतींद्र ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान मुख्तियारी को विभिन्न मुद्दों पर बुलाता है। इसलिए वह वहां जाकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य के मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही यतींद्र ने यह भी स्वीकार किया कि नेतृत्व के मुद्दे पर भ्रम की स्थिति थी।

कोई फैसला नहीं लिया है और इसे स्थगित कर दिया है। उन्होंने दावा किया इसलिए अभी तक कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं हुई है। दरअसल, 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष तेज हो गया था। यह अटकलें 2023 में सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच हुए कथित सत्ता-साझाकरण समझौते से और तेज हो गई। हालांकि, हाल ही में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों ने हाईकमान के निर्देश पर एक दूसरे के आवास पर नाश्ते पर बैठक की थीं, जिसे दोनों के बीच नेतृत्व की खींचतान को रोकने और विशेष रूप से बेलगावी विधानमंडल सत्र से पहले सिद्धरामैया के फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहने का संकेत देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इसके साथ ही यतींद्र के अनुसार कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) एक निश्चित अवधि के लिए उम्मीदवार चुनता है। सीएलपी ही तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यतींद्र ने आगे दावा किया कि हाल ही में आलोकमान की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने

सीएम कुर्सी की खींचतान में सत्र बर्बाद हो रहा

बेगलूर/रुध लाभ ब्यूरो।
विधायकसभा में विपक्ष के नेता
आर. आशोक ने भविष्यवाणी की
है कि राख से ढके गाड़ों जैसी
कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे कितीनी
भी नाशता बैठकें कर ली जाएं,
ठंडक कम होने के कोई आसार
नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस
बार में एक पोस्ट किया है, भले ही
यह बेगलूर से बेलगावी आएँ,
लेकिन उन्हें अंदर ठंड नहीं लग
रही है। उन्होंने कहा कि यह
अफसोस की बात है कि बेलगावी
राज्य, जिसे राज्य के ज्वलंत मुद्दों,
खासकर उत्तरी कर्नाटक के मुद्दों
पर चर्चा का मंच माना जाता था,
कांग्रेस पार्टी की कुर्सी की खी-

चतन में बर्बाद हो रहा है। एक तरफ सीएम सिद्धार्थों के बेटे यतींद्र अपने बचकाने बयानों से पूरे सत्र का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, डीसीएम की डीके शिवकुमार ने कहा है कि वह सदन में उपस्थित हुए बिना हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के निवेश सम्मेलन में भाग लेकर कांग्रेस आलाकमान के प्रति अपना कतिपस प्रदर्शन दे रहे हैं। कुल मिलाकर, अशोक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह अपरिहार्य है कि कन्नड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने और उन्हे सत्ता देने की गलती के लिए उरोजना पश्चाताप करना पड़ रहा है।

एक ही बच्चा होने पर भी सरकारी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री
मधु बंगारप्पा ने विधान परिषद में
स्पष्ट किया कि राज्य के सरकारी
बच्चों में भले ही केवल एक
बच्चा हो, कन्नड़ माध्यम के स्कूल
किसी भी कारण से बंद नहीं होंगे।
सदस्य निदानंद एम. गौड़ा और
उमाश्री के सवाल का जवाब देते
हुए उन्होंने कहा कि सोशल
मीडिया पर यह दुष्प्रचार चल रहा
है कि सरकारी कर्म छात्र संख्या
वाले स्कूलों को पड़ोसी स्कूलों में
विलय कर देगी या स्कूल बंद कर
दिये जायेंगे। उन्होंने इस बात पर
आक्रोश जताया कि मीडिया भी
झूठा संपर्न कर रहा है। हमने



कभी नहीं कहा कि हम कहीं भी सरकारी स्कूलों को बंद करेंगे या मर्ज करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में फैलाया गया भ्रम केवल अटकलें हैं। कुछ जगहों पर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है। हालांकि, हम उन स्कूलों को बंदी पाठ्यपुस्तकें

में नहीं बैरूंगा। एक सूत्र के मुताबिक, मौजूदा सत्र में सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना बहुत कम है। जनवरी में साल के पहले सत्र के बाद मार्च में बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। तब तक अगर वह सम्मानपूर्वक अपने पद से इस्तीफा दे दें तो सरकार इस प्रयास से पीछे हट जायेगी। अगर यह स्थिति बननी रही तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ बिना किसी औपचारिकता के अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की संभावना है। इससे पहले विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होराड़ी ने कहा था कि अगर सदन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो वह सरकार के फैसले के सामने झुकेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सरकार इस सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

लाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उन्हें झुकना होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष होने के नाते सदन को नियमों के अनुरूप चलाना मेरा कर्तव्य है और अन्य विषयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में खबर आई है कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि सदन में मेरे पास बहुत नहीं है और मुझे नैतिक इस्तीफा दे देना चाहिए। उस पर मेरी टिप्पणी से अध्यक्ष पद का सम्मान नहीं होता। उन्होंने दोहराया कि सदन में सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। बहुत महत्वा है या नहीं यह सरकार पर छोड़ दिया गया है, सदन का निर्णय अंतिम है। अगर चर्चा की बात आणी तो मैं नियमों के मुताबिक चलूंगा। लेकिन विधान परिषद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कोई इतिहास नहीं है। पिछले सत्र में मंत्री लक्ष्मी

और मध्याह्न भोजन प्रदान कर रहे हैं। क्या यह कहीं रुका है? कन्नड़ हमारे खून में है। हम कन्नड़ के लिए प्रतिबद्ध हैं। चिंता भी है। अगर अलग सरकारें सरकारी स्कूलों को बहाल स्थिति में पहुंचा दें तो यह अलग बात होगी। जब सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सहायता प्रदान स्कूलों में आवश्यक कार्यक्रम कार्यों की नियुक्ति करके वाली पहली सरकार बनी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सराहना की। मुझे सदन को बताना है कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। हमने पर देश में सरकारी

लाएगी। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उन्हें झुकना होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाना सरकार को के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अध्वक्ष होने के नाते सदन को नियमों के अनुरूप चलाना मेरा कर्तव्य है और अन्य विषयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मीडिया में खबर आई है कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि सदन में मेरे पास बहुमत नहीं है और मुझे नैतिक इस्तीफा दे देना चाहिए। उस पर मेरी टिप्पणी से अध्वक्ष पद का सम्मान नहीं होता। उन्होंने दोहराया कि सदन में सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है। बहुमत है या नहीं यह सरकार पर छोड़ा दिया गया है, सदन का निर्णय अंतिम है। अगर चर्चा की बात आएगी तो मैं नियमों के मुताबिक चलेऊंगा। लेकिन विधान परिषद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को कोई इतिहास नहीं है। पिछले सत्र में मंत्री लक्ष्मी

हेबबालकर और सीटी रवि के बीच हुए झगड़े की बात करें तो परिषद के दोनों सचिवों से चर्चा की गई जब यह घटना हुई थी। साथ ही यह मुद्दा नीति निर्धारण समिति को दिया गया। नीति निर्धारण समिति ने दो बार बैठक कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी दोनों से बात हुई है। हमें जो करना था वह हमने कर लिया है। हमने अपना काम जिम्मेदारी से किया है। कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप पर उन्होंने कहा अगर एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित हुआ तो वह एक पले के लिए भी इस पद पर नहीं रहेंगे। मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। केईए के जरिए 30 पदों पर भर्ती की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भर्ती केईए के माध्यम से होती है, हमारी भूमिका नहीं। उन्होंने कहा कि अगर विधायक दोष देना चाहते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। इस बार सदन में उत्तर कर्नाटक और उत्तराखण्ड कर्नाटक पर चर्चा को प्राथमिकता दी जायेगी। पिछले सत्र में उत्तर कर्नाटक पर 6 घंटे 35 मिनट तक बहस हुई। हर दिन उत्तर कर्नाटक की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले विषय पर चर्चा की जाएगी। उत्तरी कर्नाटक पर पूरी बहस बुधवार को की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तरी

कनार्टक के मुद्दे पर चर्चा को प्रार्थमिकता दी जाएगी। मुख्य रूप से, कोलासा बंदूरी, कृष्णा अपर बैक, रत्नाश्रम सृजन के मुद्दे पर चर्चा होगी। हम एजेंडा पूरा करेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। आगामी 19 तक सदन होगा उन्हींने कहा कि पिछले सदन में उतर कनार्टक को लेकर कुल छह घंटे 35 मिनट तक चर्चा हुई। ना-गण्डा यादव के इस आरोप पर जवाब देते हुए कि वे सदन में हेब्बालकर और सीटी रवि के बचाव में नहीं आए, उन्हींने कहा मैंने सचिवों को बैठक चर्चा की। मामला नीति निर्धारण समिति को दिया गया। समिति की दो बार बैठक हो चुकी है। इसके अलावा दो लोगों को बुलाकर जानकारी ली गई। उन्हींने बताया कि निर्णय अभी भी समिति के समक्ष है। नागराज यादव सदन के सदस्य हैं। वे एक साल बाद क्यों बात कर रहे हैं। हमने पहली बार विधायकों को अधिकार समिति में नियुक्त किया है। जो भी मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगा, मैं उसे जवाब दूंगा। उन्हींने साफ किया कि अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो मैं इस कुर्सी पर एक मिनट भी नहीं बैदूंगा। मैंने छोटे मोटे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यदि आरोप सिद्ध हो जाए और दस्तावेज न दिए जाएं तो ऐसे लोगों को कायर कहना होगा।

गीजर गैस लीक के शक से मां-बेटी की मौत

बेगलूर/शुभ लाभ ब्यूरो।

गाविवादाजनगर के पशुशाला
नगर से सामने आई एक दुखद
घटना में, एक 26 वर्षीय महिला
और उसकी चार वर्षीय बेटी का
सोमवार को कथित तौर पर
बाथरूम के गीजर से लीक हो रही
गैस के कारण मौत हो गई।
पीड़ितों की पहचान 26 वर्षीय
चांदीनी और उसकी 4 वर्षीय बेटी
युवी किरण के रूप में की गई है।
यह घटना तब हुई जब चांदीनी
अपने बच्चे को नलाने के लिए
एक ही थी। पुलिस के मुताबिक,
आशंका है कि गीजर से गैस लीक
हो गई, जिससे दोनों बेहोश हो
गए। घटना का खुलासा तब हुआ

जब पति किरण ने अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लाने के लिए पचास चांदनी को फोन किया, तो किरण को चौंकी जवाब नहीं मिला। जब किरण उस तक नहीं पहुंच पाया तो उसने अपने छोटे भाई को अपनी बेटी को लाने के लिए भेजा। दोनों स्कूल से लौटे और देखाजाचा अंदर से बंद पाया। उसने तुरंत जबरदस्ती दवाजा खोला और दोनों को बाथरूम में पड़ा हुआ पाया। उन्होंने जब्तोरियाया अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सीयाय के बावजूद, हलाय का प्रयास भी असर न होतू, इलाज की मृत्यु हो गई। चांदनी के पति किरण बर्दई का काम करते हैं।

ई-एफआईआर पूरे कश्मीर में पुलिसिंग को बदलने लगी है

सुरेश एस डुगार

जम्मू, 9 दिसम्बर। एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव पूरी कश्मीर वादी में पुलिस व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद से, ई-एफआईआर प्रणाली सबसे प्रभावशाली सुधारों में से एक के रूप में उभरी है, जो निवासियों को घर से अपराधों की रिपोर्ट करने का एक तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी तरीका प्रदान कर रही है।श्रीनगर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि नए कानूनी ढांचे ने क्षेत्र में प्रिपोटिंग की गति को बदल दिया है। अधिकारी का कहना था कि ई-एफआईआर सुविधा ने देरी को कम कर दिया है और आम नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करना अधिक सुलभ बना दिया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि श्रीनगर इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है, इस साल 30 ई-एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। जबकि अन्य जिलों में संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि अधिक से अधिक निवासी सिस्टम के बारे में सीख रहे हैं और डिजिटल प्लेटफार्म पर विश्वास हासिल कर रहे हैं।श्रीनगर में कई लोगों के लिए इस बदलाव ने



लंबे समय से चली आ रही झिझक को दूर कर दिया है। लाल बाजार की रूकैया बशीर ने बताया कि उन्हें आनलाइन शिकायत दर्ज करने में अधिक आसानी महसूस हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन में घूमना तनावपूर्ण हो सकता है। ई-एफआईआर के साथ, मैंने घर से कुछ ही मिनटों में सब कुछ जमा कर दिया। यह सुरक्षित और सरल लगा।इसी तरहसे राजबाग के निवासी समीर मीर के बकौल, प्रणाली बहुत जरूरी स्पष्टता लेकर आई है। वे कहते थे कि हर चीज तुरंत स्वीकार कर ली जाती है। आप अपडेट देख सकते हैं और प्रगति का अनुसरण कर सकते हैं। इस तरह की पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है।

कारोबारी समुदाय ने भी इस बदलाव का स्वागत किया है। महाराज गंज में एक दुकान चलाने वाले बिलाल अहमद कहते थे कि प्रक्रिया अब अधिक पूर्वानुमानित लगती है। उन्होंने कहा कि पहले, कागजी कार्रवाई में समय लग सकता था और आपको हमेशा यह नहीं पता होता था कि आपकी शिकायत किस स्तर पर है। अब अपडेट आनलाइन हैं और उन्हें ट्रैक करना आसान है।

श्रीनगर में युवाओं का कहना है कि यह प्रणाली स्वाभाविक रूप से उनके दैनिक जीवन में फिट बैठती है। बेमिमा की एक छात्रा जैनब शफीक ने बताया कि आनलाइन एफआईआर दर्ज करना आधुनिक और सुविधाजनक लगता है। वे कहती थीं कि हम पहले से ही अपना ज्यादातर काम आनलाइन करते हैं। किसी अपराध की डिजिटल रूप से रिपोर्ट करना सही कदम लगता है।पुलिस का कहना है कि डिजिटल इंटरफेस ने कागजी कार्रवाई को कम करने, निगरानी में सुधार और प्रतिक्रिया समय में तेजी लाकर उन्हें आंतरिक रूप से मदद की है।जैसे-जैसे कश्मीर स्मार्ट प्रशासन की ओर बढ़ रहा है, ई-एफआईआर का उदय एक बड़ा कदम है - जिससे न्याय त्वरित, अधिक सुलभ और सभी के लिए बस एक क्लिक दूर हो गया है।

सीमा पार आतंकी फिर जुटने लगे लांचिंग पैडों पर



जम्मू, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। सुरक्षाधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि सीमा पार लांचिंग पैडों पर आतंकी एक बार फिर घुसपैठ के लिए जुटने लगे हैं। उनका कहना है कि आतंकी अब फिर से सीमा पार लांचिंग पैड पर एकत्रित होने लगे हैं। खबरों के मुताबिक सीमा पार आतंकी संगठनों के प्रमुख और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिलकर भारी तादाद में आतंकी घुसपैठियों को सीमा पार करवाने की तैयारी कर ली है।उल्लेखनीय है कि बर्फबारी के समय में आतंकी घुसपैठ की वारदात बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर अब बिलों में दुबके आतंकी एक बार फिर से लांचिंग पैडों पर जमा होने लगे हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकीयों को लांचिंग पैडों से हटाकर काराक टेरर कैंपों में भेजा गया था। अब सीमा पार लांचिंग

पैड पर आतंकीयों की हलचल फिर बढ़ी है।मालूम हो कि एलओसी से 4.5 किलोमीटर दूर ये लांचिंग पैड हैं। खबरों के मुताबिक, एलओसी के पार करीब 42 लांचिंग पैड पर ये आतंकी देखे गए हैं। पाक सेना की मदद से लांचिंग पैड पर आतंकीयों को फिर पहुंचाया गया है।बताया जाता है कि सीमा पार करीब 42 लांचिंग पैड पर आतंकी मौजूद हैं। नौशहरा, केरन में सीमा पार लांचिंग पैड पर आतंकी देखे गए हैं। साथ ही टंगधार, रामपुर में भी सीमा पार लांचिंग पैड पर आतंकीयों की मौजूदगी देखी गई है। इन आतंकीयों को सैन्य शिविरों से निकाल कर पाक सेना सीमा पर अपनी पोस्टों पर ले आई है और यहां से ही इन्हें घुसपैठ करने के लिए भेजे जाने की पूरी तैयारी है। आतंकीयों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है।

सेना के सूत्रों के मुताबिक अभी हाल ही में उस पार आतंकी संगठनों और आईएसआई के अधिकारियों की बैठक में घुसपैठ के लिए रणनीति बनाई गई। बैकव में इस बात पर जोर दिया गया कि पहाड़ों व नालों में बर्फ गिरने से पहले घुसपैठ में तेजी लाई जाए और जल्द आतंकीयों को सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में पहुंचाया जाए।

सीएम ममता बनर्जी ने मनरेगा योजना के लिए केंद्र की शर्तों का किया विरोध

कोलकाता, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 100 दिन की नौकरी योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नए पात्रता मानदंड का विरोध किया। उन्होंने कूचबिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) विरोधी रैली को संबोधित करते हुए इस मामले में केंद्र की नई शर्तों का विरोध करते हुए उनकी मसौदा प्रति भी फाड़ दी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि



कुछ दिन पहले हमें नए श्रम संहिता पर एक नोटिस मिला। केंद्र सरकार ने 100 दिन की रोजगार योजना की पात्रता के लिए नई शर्तें लगाई थीं। मैं ऐसी शर्तों से सहमत नहीं हूं। ये शर्तें अपमानजनक प्रकृति की हैं, इसलिए मैं नोटिस की एक प्रति फाड़ रही हूं। यह मेरे लिए

कोई केंद्रीय नोटिस नहीं है, बल्कि यह मेरे लिए बस एक कोरा कागज है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को 100 दिन की नौकरी योजना के लिए केंद्र सरकार से अभी तक 51,617 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं मिली है।उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय कोष की परवाह नहीं है। अगर अगले साल विधानसभा चुनावों के बाद गुणमूल कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो हम राज्य की अपनी 100 दिन की नौकरी योजना शुरू करेंगे।

बिहार कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी, महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाया

पटना, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल के पहले बड़ा तोहफा दिया। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को नए 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त



कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह एक जुलाई 2025 से मान्य होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभागों के गठन की भी मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार में अब 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग का गठन किया जा रहा है। इनमें युवा रोजगार

एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल हैं। इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग करने को लेकर मंजूरी मिली है। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला

एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिल गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान करना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय' करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में गया जी एवं मुंगेर जिला को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने और उनमें नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के कुल 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

कोर्ट ने गुजरात के पूर्व डीएम को सुनाई 5 साल की सजा, सरकार को 1.20 करोड़ रुपए का पहुंचाया था नुकसान

अहमदाबाद, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। विशेष पीएमएलए अदालत ने भुज भूमि आवंटन के दौरान गुजरात सरकार को 1.20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए एक पूर्व जिला कलेक्टर को पांच साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी। शनिवार को कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा को सजा सुनाते हुए केंद्र सरकार को उसकी 1.32 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, जिसे ईडी ने एक दशक पुराने अपराधों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के दौरान जब्त किया था। प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा जब भुज (कच्छ) में जिला कलेक्टर के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरकारी जमीन कम दरों पर आवंटित की। इससे गुजरात सरकार को 1.20 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ। ईडी के बयान में कहा गया है कि तत्कालीन कलेक्टर ने आपराधिक गतिविधियों के संबंध में अनुचित मौद्रिक लाभ प्राप्त किए। जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण



अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुजरात के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। शनिवार को अहमदाबाद में विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसकी इस अपील को खारिज कर दिया कि इस पीएमएलए मामले में उसकी अगली सजा पिछली सजा के साथ-साथ चलाने का आदेश दिया जाए।स्पेशल कोर्ट ने कहा कि प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा एक आईएएस अधिकारी था और जिला मजिस्ट्रेट के पद पर था। उसने भ्रष्टाचार कर और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होकर अपने

आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने कहा कि दोनों अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पीएमएलए, 2002 के तहत अलग-अलग हैं। दोनों कानून खास मकसद से बनाए गए हैं।स्पेशल कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा में एकरूपता का निर्देश देने का कोई उचित कारण नहीं है और तदनुसार, अभियुक्त का यह अनुरोध कि इस मामले में उसकी अगली सजा को उसकी पिछली सजा के साथ-साथ चलाने का आदेश दिया जाए, अस्वीकार किया जाता है। इससे पहले, प्रदीप निरंकरनाथ शर्मा द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा था कि कानून मानता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्थिर घटना नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली गतिविधि है, जब तक कि अवैध लाभ अर्जित किया जाता है, उसे वैध के रूप में पेश किया जाता है या अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल किया जाता है। इस प्रकार यह तर्क कि अपराध जारी नहीं है, कानून या तथ्यों के आधार पर सही नहीं है और इसलिए इस आधार पर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता।

एके. शर्मा पहुंचे खानपुर,किया बिजली बिल राहत योजना शिविर का निरीक्षण

लखनऊ, 9 दिसंबर (एजेंसियां)।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पहुंचे जौनपुर, खानपुर ग्राम में बिजली बिल राहत योजना शिविर का निरीक्षण किया। शिविर की व्यवस्थाओं, पंजीकरण प्रक्रिया तथा लाभार्थियों को मिल रही जानकारी का मूल्यांकन किया। मंत्री ने कहा, उपभोक्ताओं को योजना की सही जानकारी और सहज सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में बोते दिवस 80 विद्युत उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। कई उपभोक्ता लंबे समय से बकाया बिल को लेकर परेशान थे लेकिन योजना के प्रति मिले सकारात्मक माहौल ने उनमें राहत और विश्वास बढ़ाया। उपभोक्ताओं ने सरकार की ओर से दी जा रही ऐतिहासिक सहायता बताया, जिससे उनके आर्थिक बोझ में भारी कमी आएगी।निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की कि 31 मार्च के बाद भुगतान करने वाले उपभोक्ता भी अब बिजली बिल राहत योजना का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे सभी पात्र उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर उन्हें योजना से जोड़ने की प्रक्रिया तेज़ की जाए। सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र उपभोक्ता लाभ से वंचित न रहे।ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली का बकाया है, वे अवश्य पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाएं। पहले चरण में 31 दिसंबर तक पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 फीसदी तक की विशेष छूट दी जाएगी। इसके बाद यह छूट कम हो जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में ही अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाने की सलाह दी। योजना प्रदेश सरकार की गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने की एक ऐतिहासिक पहल है। गांव-गांव शिविर आयोजित कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुविधा सीधे लोगों तक पहुंचे और उन्हें किसी भी स्तर पर कठिनाई का सामना न करना पड़े।

ए राजा के बयान पर साक्षी महाराज का तंज ‘ऐसी ही बात जिन्ना ने भी कही थी’

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने मंगलवार को डीएमके सांसद ए राजा के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने देते मातरम को मुसलमानों के खिलाफ बताया था।



सांसद साक्षी महाराज ने आईएनएस से बातचीत में दावा किया कि ए राजा से पहले इसी तरह का बयान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दिया था। उन्होंने भी वंदे मातरम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया था, जिसके दबाव में आकर पंडित नेहरू को इसे वापस लेना पड़ा था। ऐसे लोग देश को विभाजित करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के सपने किसी भी कीमत पर पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चर्चा के लिए होती है, शोर मचाने के लिए नहीं। हमें उम्मीद है कि संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का रवैया सकारात्मक रहेगा। सदन में चर्चा के दौरान किसी भी प्रकार की खलल पैदा नहीं होगी। विपक्ष की तरफ से अगर सकारात्मक रवैया रहेगा, तो हर

मुद्दे पर लोकतांत्रिक ढंग से चर्चा संभव हो पाएगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में मुख्य रूप से जनता का हित निहित था। उनके संबोधन में लोगों की फिक्र साफतौर पर झलक रही थी। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि कैसे लोगों का व्यक्तिगत विकास हो और उनके विकास के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए।उन्होंने कहा कि किसी को भी देश में मतदाता

सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की प्रक्रिया जरूरी हो जाती है, क्योंकि फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करके सिर्फ पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यह समझ से परे है कि किसी राजनीतिक दल को इससे क्या आपत्ति हो रही है। उन्होंने बिहार में संपन्न हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर भी प्रतिक्रिया दी।

घर हो या दुकान, बिना सत्यापन न रखें ‘नौकर’: योगी

लखनऊ, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज नागरिकों से अपील की कि वे सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान का अवश्य सत्यापन करें।उन्होंने कहा कि उजर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंया और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त एवं निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने अपील ऐसे समय की है, जब पिछले सप्ताह से प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। उन्होंने आज सुबह 'एक्स' पर एक पोस्ट में उच्चतम न्यायालय

की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा, "उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं।मुख्यमंत्री ने कहा, संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है घुसपैठियों का नहीं। राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंया और बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध सघन अभियान शुरू किया गया है तथा शहरी स्थानीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने का निर्देश है।

यथींद्र की दो टूक,‘कर्नाटक में सीएम नहीं बदलेगा, सिद्धारमैया ही पूरा करेंगे कार्यकाल’

बेलगावी, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बयानबाजी जारी है। इस पर बीते दिन (सोमवार को) मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र और कांग्रेस एमएलसी यथींद्र सिद्धारमैया ने कहा था कि हाई कमान ने स्पष्ट किया है कि सीएम पद में कोई बदलाव नहीं होगा। अब उन्होंने मंगलवार को अपने बयान को दोहराया है। यथींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के दावे को हाई कमान ने स्वीकार नहीं किया है और उनके पिता सिद्धारमैया अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। सुवर्ण सौध (विधानसभा) में पत्रकारों से बातचीत में यथींद्र ने कहा, मैं अपनी बात पर पूरी तरह कायम हूं। जो कहना था कह दिया है। अब इस विषय पर बार-बार प्रतिक्रिया देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लोग कुछ भी कहें, मैं अब इस मुद्दे पर और नहीं बोलूंगा। शहरी विकास मंत्री बिराधी सुरेश से पूछा गया कि क्या पार्टी के भीतर भविष्य के नेतृत्व पर कोई चर्चा हुई है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हमारे नेता सिद्धारमैया ही हैं। भविष्य के नेता का फैसला भी वहीं और हाई कमान मिलकर करेंगे। हाई कमान की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होगा।



उन्होंने कहा, हाई कमान है और हम उसके फैसले का पालन करेंगे। राजा जिंदा है, भले ही लोकतंत्र में इस तरह कहना उचित न हो, लेकिन हमारे नेता ही आगे का निर्णय करेंगे।यथींद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश ने कहा, व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की सही को स्वतंत्रता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार दोनों कह चुके हैं कि वे हाई कमान के फैसले का सम्मान करेंगे। हम सभी भी इसी रुख पर हैं।

कांग्रेस विधायक बेतूरू गोपालकृष्णा ने इस विवाद को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के

किसी भी कीमत पर अवैध खनन और बिक्री बर्दाश्त नहीं : विजय सिन्हा

पटना, 9 दिसंबर (एजेंसियां)। बिहार में अवैध बालू खनन और बिक्री के खिलाफ सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर अवैध खनन और उसकी बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दीपा क्षेत्र के आसपास मध्यरात्रि में अवैध रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली के परिचालन की सूचना मिलते ही तत्काल सज्जान लेते हुए पटना के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दहन तथा अन्य खनन पदाधिकारियों के साथ आपात बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। इसके उपरांत मध्यरात्रि में छापेमारी अभियान चलाते हुए खनन विभाग द्वारा कुल 28 अवैध वाहनों को जब्त किया गया और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट संदेश है कि अवैध खनन किसी भी



परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ निर्णायक और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य की प्राकृतिक संपदा की रक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस थाने से अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर गुजरते हैं, वहां सीसीटीवी लगे हैं। अगर फिर भी

कार्रवाई नहीं हो रही तो यह थाना प्रभारी की लापरवाही है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कारोबार में थाना प्रभारियों की मिलीभगत सामने आई तो सख्त कार्रवाई तय है।

डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार पर ‘जिरो टॉलरेंस’ नीति का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अवैध बालू कारोबार या ओवरलोडिंग की सूचना देता है तो उसे 'योद्धा' मानकर 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।

सिन्हा ने कहा कि खनन विभाग में पिछले वर्षों में कई बेहतर काम हुए हैं। अधिकारियों, सचिवों और पूरी टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।



देश को विभाजित करने वाले जयचंद और मीरजाफर जैसे पापी : योगी

गोरखपुर, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज और देश को विभाजित करने वालों से सावधान रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे लोग जयचंद और मीरजाफर जैसा पाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तोड़ने के लिए बहुत से लोग हैं। कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र और कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है। समाज और देश तोड़क इन तत्वों को जब सत्ता में आने का मौका मिलता है तो वे सिर्फ अपने और परिवार के बारे में सोचते हैं। परिवार के लिए प्रॉर्टी, विदेश में होटल और द्वीप खरीदते हैं। ऐसे लोग देश को दरिद्र करने का षड्यंत्र करते हैं। जाति, क्षेत्र आदि के नाम के तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज और देश का कल्याण नहीं हो सकता। देश का कल्याण तभी होगा, जब भेदभाव नहीं होगा, सबमें एकता होगी। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को सैनिक स्कूल गोरखपुर में देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) जनरल बिपिन रावत के नाम पर बने ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण किया और महान सैन्य नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस प्रतिमा की स्थापना जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कराई गई है। मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के जीवन पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को याद किया तथा देश के



समसामयिक हालात पर भी चर्चा करते हुए विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिलाए गए पंच प्रणों को अपनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि आजादी के शताब्दी वर्ष तक हमें कैसा भारत चाहिए, इसके लिए एक कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई सच्चा भारतीय गरीब, असुरक्षित या कमजोर भारत चाहता होगा? इसका जवाब भी उन्होंने खुद दिया और कहा कि एक सच्चा भारतीय मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर भारत ही चाहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है तो वह सच्चा भारतीय हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को अगर विकसित और सुरक्षित बनाना है तो पीएम मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रणों को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि

हमें अपने वीरसैनिकों और महापुरुषों का सम्मान करना होगा। श्रीराम, श्रीकृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई की विरासत और परंपरा पर गर्व करना होगा। अपनी विरासत और परंपरा को नजरअंदाज करके समाज प्रगति नहीं कर सकता। इसमें किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। देश में बनी चीज खराब और विदेशी अच्छा है, इस सोच को तिलांजलि देनी होगी। असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने कहा कि सैन्य सेवा के जरिए जनरल बिपिन रावत का देश हित में योगदान स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। वह बिना भय अपनी बात रखने वाले बेबाक इंसान थे। सैनिक जीवन में भावुकता का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। जनरल रावत इसे खूब समझते थे। उन्होंने कठोराता और संयम के बीच समन्वय बनाते हुए कभी दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं होने दिया। उन्होंने जो राह बनाई वह सभी सैनिकों के लिए आदर्श और प्रेरक हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सैनिक स्कूल को दिया गया ऑडिटोरियम का उपहार सदैव स्मरणीय रहेगा। यह सीएम योगी की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। इससे जनरल बिपिन रावत के नाम से वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी।

74 फीसदी परिषदीय स्कूल में शुरू हो जाएगी स्मार्ट क्लास

लखनऊ, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रदेश की 74 फीसदी परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश के अनुपातिक रूप से मात्र 46.79 फीसदी परिषदीय स्कूलों में ही स्मार्ट क्लास की सुविधा है। इसमें परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों से लेकर कम्पोजिट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी आते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के लिए 'वाई-फाई' सुविधा से पूरी तरह लैस करने की संस्तुति की गई है स्कूलों को पूरी तरह से इंटरनेट सुविधा से लैस करने के निर्देश हैं। बेसिक शिक्षा के अलग-अलग क्षेत्रों में कई कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी यूपी स्मार्ट क्लास के मामले में अभी भी देश के कई राज्यों से पीछे है। समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू की गई है। कई स्कूलों में सीएनआर कॉर्पोरेट सोशल रिसर्प्सिबिलिटी फण्ड से भी स्मार्ट क्लास शुरू कराए गए हैं। स्मार्ट क्लास नियमित रूप से संचालित होती रहें, बड़ी संख्या में बकायदा आईसीटी लैब की स्थापना भी की गई है लेकिन

यूपी जैसे बड़े राज्य एवं स्कूलों की अधिक संख्या वाले प्रदेश में यह संख्या 'ऊंट के मुंह में जिरा' जैसी है। जिलेवार स्थितियों को देखें तो कई जिले तो ऐसे हैं, जहां अभी भी लक्ष्य से काफी कम स्मार्ट क्लास शुरू किए जा सके हैं। वहीं तमाम जिले ऐसे में जहां स्मार्ट क्लास तैयार तो हो गए लेकिन इंटरनेट कनेक्शन न होने या उपकरणों के निष्क्रिय पड़े होने के कारण नॉन फंक्शनल स्मार्ट क्लास के रूप में हैं। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही बिना इंटरनेट या निष्क्रिय उपकरणों वाले स्मार्ट क्लास को पूरी तरह से सक्रिय कराने की दिशा में काम शुरू करने जा रही है। लक्ष्य 31 मार्च 2026 रखा गया है जिससे पहले निष्क्रिय स्मार्ट क्लासों को तो शुरू किया ही जाएगा, नए स्मार्ट क्लास शुरू कराने की योजना है। शुरूआत नॉन फंक्शनल स्मार्ट क्लास से किया जाएगा। ऐसे जिले जहां 10 फीसदी से भी कम है। स्मार्ट क्लास के सक्रिय उपकरण जिले का नाम नॉन फंक्शनल स्मार्ट क्लास प्रतिशत में हरेदोई 10 संभल 9.76 बिजनौर 9.47 बदायूं 9.44 मुर्दाबाद 8.41 मथुरा 8.24 बरेली 8.21 भदोही 7.95 मुजफ्फरनगर 6.92 शाहजहांपुर 6.76 है।

एसआईआर की समय-सीमा बढ़े, बैलेट पेपर वापस लाया जाए : मायावती

लखनऊ, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। संसद में चुनाव सुधार पर जारी चर्चा के बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के लिए तीन महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की है। पार्टी का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की वर्तमान समय-सीमा बेहद कम है, जिससे बीएलओ पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और इससे वैध मतदाताओं, विशेषकर गरीब और प्रवासी मजदूरों, के नाम मतदाता सूची से छूटने का जोखिम बढ़ गया है। मायावती ने कहा कि जहां करोड़ों मतदाता हैं, वहां एसआईआर प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा करने का प्रयास उचित नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 15.40 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और निकट भविष्य में कोई चुनाव भी निर्धारित नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट कहा कि जल्दबाजी के चलते अनेक वैध मतदाता-जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक मतदान अधिकार के पात्र हैं-सूची से वंचित हो सकते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है, इसलिए एसआईआर की समय-सीमा को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। मायावती ने आपराधिक मामलों के खुलासे से जुड़े



सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार प्रत्याशी को अपने आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण हलफनामे और स्थानीय अखबारों में प्रकाशित करना होता है, जबकि पार्टी को भी वही जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रत्याशी अपना आपराधिक इतिहास पार्टी से छुपा लेते हैं और यह जानकारी स्कूटी की दौरेन सामने आती है, जिससे अनावश्यक दायित्व पार्टी पर आ जाता है। पार्टी ने सुझाव दिया है कि

आपराधिक मामलों के संबंध में सभी औपचारिकताओं की जिम्मेदारी सीधे प्रत्याशी पर ही डाली जानी चाहिए, न कि राजनीतिक दलों पर। अगर कोई प्रत्याशी अपने आपराधिक मामले छुपाता है, तो उससे जुड़ी सभी कानूनी जिम्मेदारियां भी उसी पर तय हों, पार्टी पर नहीं। ईवीएम को लेकर उठने वाले संदेहों पर भी बीएसपी मुखिया ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए अब ईवीएम की जगह फिर से बैलेट पेपर द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह त्वरित रूप से संभव न हो, तो कम से कम हर बूथ पर वीवीपैट की सभी पंक्तियों की गिनती कर उसे ईवीएम के आंकड़ों से मिलान किया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के उस तर्क को भी खारिज किया कि इससे समय अधिक लगेगा। मायावती ने कहा कि जब पूरे चुनाव की प्रक्रिया महीनों चलती है, तो कुछ अतिरिक्त घंटे गिनती में लगने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे जनता का चुनाव व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले संदेहों का अंत होगा, जो देशहित में है।

अयोध्या में एसआईआर प्रक्रिया तेज, विधायक वेद प्रकाश बोले – सही और साफ वोटर लिस्ट हमारी प्राथमिकता

अयोध्या, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति पर बात करते हुए विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि यह काम अभी चल रहा है। हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह सही और अपडेटेड हो। कई सालों से वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम जुड़े थे जो अब इस दुनिया में हैं भी नहीं, जबकि कई लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या जिनका रिकॉर्ड ठीक से अपडेट नहीं हुआ। उनका हकना है कि इससे चुनाव वाले दिन कई तरह की दिक्कतें आती थीं। किसी का नाम बूथ पर नहीं मिलता, किसी का नाम किसी दूसरे इलाके



में चला जाता और कभी-कभी फर्जी वोटिंग की भी आशंका बन जाती थी। ऐसे में एसआईआर कराना बहुत अच्छा है। विधायक ने बताया कि आज प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस प्रक्रिया की समीक्षा

करने अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम सब लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी असली और पात्र वोटर हैं, उनके नाम पक्के तौर पर वोटर लिस्ट में हों और जिन लोगों का निधन हो चुका है या जो यहां से चले गए हैं, उनके नाम समय पर हट जाएं। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और चुनाव के दिन होने वाली गड़बड़ाइयों से बचाव होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में जब वोटर लिस्ट को सही तरीके से दुरुस्त किया गया तो मतदान प्रतिशत 70 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया। इसका कारण यही था कि मृतक और फर्जी नाम हटने के बाद असली वोटरों

पर फोकस बढ़ा और लोग भी ज्यादा जागरूक हुए। अयोध्या में भी यही प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि आज महिलाएं, बेटियां और युवा मतदाता खुद अपना वोट बनवाने के लिए आगे आ रहे हैं। जो युवा अभी-अभी 18 साल के हुए हैं, उनका नाम भी सही तरीके से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, "हमारा मकसद है कि हर पात्र नागरिक को वोट डालने का पूरा मौका मिले और कोई भी गलत तरीके से लिस्ट से बाहर न रह जाए।" उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार की वोटर लिस्ट पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा सटीक, व्यवस्थित और पूरी होगी।

वंदे मातरम् पर विवाद के बजाय एकता और भाईचारे पर ध्यान देना चाहिए : मौलाना शहाबुद्दीन

बरेली, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में सोमवार को विशेष चर्चा हुई। इसी मुद्दे पर मंगलवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आईएनएस से बातचीत की और अपनी राय साझा की। उन्होंने अपील की कि वंदे मातरम् पर विवाद के बजाय देश की एकता, भाईचारे और आपसी सम्मान पर ध्यान देना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि इन दिनों लोकसभा में वंदे मातरम् को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वह बेवजह है। इस गीत को आए हुए 150 साल हो चुके हैं और आज इसकी 150वीं सालगिरह पर भी नेता अपनी-अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके नज़रिए से वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत है और जिसे



यह पसंद है वह इसे पूरी आजादी के साथ पढ़ सकता है। किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग किसी वजह से वंदे मातरम् नहीं पढ़ना चाहते, उन पर किसी तरह का दबाव डालना गलत है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी मान्यता, अपनी सुविधा और अपने विवेक के मुताबिक फैसला लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी को यह कहना कि तुम्हें हर हाल में यह गीत करना ही है, यह बात ठीक नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला भी दिया जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के बाद साफ कहा गया था कि किसी भी छात्र या नागरिक पर वंदे मातरम् पढ़ने का दबाव नहीं बनाया जा सकता।

गौतमबुद्धनगर में बार-रेस्टोरेंट की सघन चेकिंग जारी नव वर्ष से पहले सुरक्षा इंतजामों पर प्रशासन सख्त



नोएडा, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। गोवा के नाइट क्लब में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गौतमबुद्धनगर प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। जन-सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की ओर से जिलेभर में बार, रेस्टोरेंट और विभिन्न मनोरंजन स्थलों की संयुक्त सघन जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में मुख्य अग्रिमन अधिकारी (सीएफओ), फायर सर्विस विभाग, आबकारी विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीमें शामिल हैं, जो सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच कर रही हैं। अधिकारियों

के अनुसार, इस चेकिंग अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के किसी भी बार या मनोरंजन स्थल में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा या जन-सुरक्षा नियमों की अनदेखी न होने पाए। गोवा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन ने सभी संवेदनशील स्थानों पर औचक निरीक्षण तेज कर दिया है। अब तक लगभग 50 बार और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान टीमों द्वारा आपातकालीन निकास द्वारों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे उपकरणों की वैधता और स्थिति, इलेक्ट्रिकल वायरिंग,

अर्थिंग और ओवरलोडिंग की संभावनाओं की गहन जांच की जा रही है। साथ ही गैस सिलिंडरों की सुरक्षित स्थिति, वेंटिलेशन और स्मोक भेनजमेट, निर्धारित क्षमता के अनुरूप भीड़ नियंत्रण और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन भी प्रमुख रूप से किया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, अधिकांश प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानक संतोषजनक पाए गए हैं, वहीं कुछ स्थानों पर कमियां मिली हैं जिन पर तत्काल सुधार के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी नववर्ष समारोह को देखते हुए प्रशासन ने चेकिंग को और अधिक प्रभावी और तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भीड़भाड़ के बीच किसी भी अग्रिम घटना की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। पुलिस कमिश्नर ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे अग्नि, विद्युत और जन-सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करें। साथ ही आम नागरिकों से भी आग्रह किया गया है कि यदि उन्हें किसी मनोरंजन स्थल पर सुरक्षा संबंधी कमी नजर आए, तो संबंधित विभाग को तुरंत जानकारी दें, जिससे समय पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मेरठ में पुलिस और गोकशों में मुठभेड़ गोली लगाने से एक बदमाश घायल

मेरठ, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना पुलिस और गोकशी वाले गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश पर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना सोमवार देर रात दौलता नहर पटरी के पास एक बाग के किनारे हुई, जब बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि किस्थानी थाना क्षेत्र में दौलता नहर पटरी के पास कुछ लोग गोकशी की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही सरधना क्षेत्र की गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू की। घेराव होते ही आरोपियों ने पुलिस पर गोलाबाजी चलाई। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान नवाबुद्दीन के रूप में हुई, जो थाना दौलता क्षेत्र के



रुआसा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ गोकशी, अवैध हथियार, पशु क्रूरता समेत एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक 315 बोर का तनांचा, कारतूस, तेज धार वाले उपकरण बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मौके पर ही गोकशी की तैयारी कर रहे थे। दोनों फरार आरोपियों की पहचान पुलिस कर चुकी है और

उनकी तलाश में जंगलों और नहर पटरी क्षेत्र में कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पुलिस ने आसपास के गांवों में भी चेकिंग बढ़ा दी है ताकि आरोपी बाहर न निकल सकें। सरधना सीओ आशुतोष कुमार ने बताया, हमें सूचना मिली थी कि दौलता नहर पटरी के किनारे कुछ लोग गोकशी करने की तैयारी में हैं। पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक

आरोपी घायल हुआ और दो फरार हो गए। घायल आरोपी नवाबुद्दीन पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फॉरेंसिक यूनिट को बुला लिया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के सरधना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गश्त और निगरानी और अधिक सख्त कर दी है। फरार दोनों गोकशों के जल्द पकड़े जाने की संभावना जताई जा रही है।

बुधवार, 10 दिसंबर, 2025

बंगलूरू

सम्पादकीय

7

संपादकीय

बाबरी बनाम राम मंदिर

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूँ कबीर ने कुछ मुस्लिम चेहरों के साथ बाबरी मस्जिद की नाँव रखी, तो दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस, बाबा बागेश्वर और कई साधु-संतों ने, एक व्यापक जन-सैलाब के साथ, ‘गीता पाठ’ किया। बाबरी मस्जिद से 11 किमी की दूरी पर ‘बहरामपुर’ में राम मंदिर बनाने का उद्घोष किया गया। इन दोनों फैसलों और कर्मकांडों का धार्मिक आस्था से कोई सरोकार नहीं है। ये सांप्रदायिक, हिंदू बनाम मुसलमान, जमावड़े थे, जिनकी मानसिकता में अप्रैल-मई, 2026 के विधानसभा चुनाव उमड़-चुमड़ रहे थे। बेशक प्रभु श्रीराम समूचे भारत के जनमानस के सबसे अधिक स्वीकार्य और पूजनीय आराध्य हैं। राम के जीवन-चरित पर सबसे अधिक, प्रमुख भाषाओं में, ‘रामायण’ का सृजन किया गया है। यदि हमारे आराध्य का एक और मंदिर बनाया जात है, तो वह विवादास्पद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू ‘मूर्ति पूजक’ हैं, लेकिन श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या का भव्य मंदिर बन चुका है। मंदिर के शिखर पर सनातन की प्रतीक ‘धर्म-ध्वजा’ भी

सुशोभित की जा चुकी है। देश भर से लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य श्रीराम के दर्शन करने और मत्था टेकने अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर का सम्मान किसी तीर्थ-स्थान से कमतर नहीं है, लिहाजा एक और राम मंदिर के उद्घोष का औचित्य क्या है? देश में आज भी प्रभु राम के असंख्य मंदिर हैं, जहां अनवरत पूजा-पाठ जारी है। बेशक राम के नाम पर धुरवीकरण और सामुदायिक लाभबंदी जरूर की जा सकती है। चुनाव के मद्देनजर उनका महत्व भी निर्णायक हैं। यकीनन हिंदुओं अथवा ऐसे आस्थावानों के ध्रुवीकरण से भाजपा को चुनाव के घुवौकरण से भाजपा को चुनावी फायदा सर्वाधिक होता रहा है। स्वतंत्र भारत में बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं के स्मारक के तौर पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत अब एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है, उसमें बाबर का स्मारक स्वीकार्य नहीं है। मुस्लिम मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो सरकार से बाकायदा इजाजत लें और पैगंबर मुहम्मद के नाम पर मस्जिद बनाएं। किसे आपत्ति होगी? हालांकि राजधानी दिल्ली में ‘बाबर रोड’ आज भी मौजूद है। ऐसे और भी स्मारक बाबर के नाम पर देश में होंगे, लेकिन नए प्रयास, नए शिलान्यास, नए निर्माणों को बंद होना देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कथित बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखने देनी चाहिए थी। भाजपा के जो चेहरे चीखा-चिल्ला कर बाबरी का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी नींव का पुरजोर विरोध करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को अपने ही बागी विधायक को गिरफ्तार कराना चाहिए था, लेकिन बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रख दी गई और वह तबका का नाँव सांप्रदायिकता में कामयाब रहा। ममता को मुर्शिदाबाद की 24 विधानसभा सीटों पर 65 फीसदी से ज्यादा मुसलमानों के वोट की चिंता थी, तो ममता हिंदुओं के वोट भी छोड़ नहीं सकती थी। बंगाल में 35-40 फीसदी हिंदू वोट ममता की पार्टी के पक्ष में भी जाते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने विधायक को निलंबित ही किया। हुमायूँ कबीर ने 6 दिसंबर की तारीख इसलिए तय की थी, क्योंकि 1992 में इसी तारीख को अयोध्या की कथित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। मुसलमानों के एक तबके में आज भी उस घटना के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है। मुसलमान उस विध्वंस को ‘पाक मस्जिद की शहादत’ करार देते हैं। उसी जमीन पर सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ के फैसले के बाद राम मंदिर बना है। अदालत ने मस्जिद की वैकल्पिक जगह जहां देने का भी आदेश दिया था, उसे मुसलमानों ने न तो लिया है, मस्जिद निर्माण तो बहुत दूर को कौड़ी है। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की कथित नाँव रखी गई है, उसके निर्माण को पैसा कहाँ से आएगा।

कुछ अलग तय की थी, क्योंकि 1992 में इसी तारीख को अयोध्या की कथित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। मुसलमानों के एक तबके में आज भी उस घटना के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है। मुसलमान उस विध्वंस को ‘पाक मस्जिद की शहादत’ करार देते हैं। उसी जमीन पर सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ के फैसले के बाद राम मंदिर बना है। अदालत ने मस्जिद की वैकल्पिक जगह जहां देने का भी आदेश दिया था, उसे मुसलमानों ने न तो लिया है, मस्जिद निर्माण तो बहुत दूर को कौड़ी है। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की कथित नाँव रखी गई है, उसके निर्माण को पैसा कहाँ से आएगा।

स्वादुओ (साधुओं)। मौसम सर्दी का है। देश की राजधानी में बैठ कर, मैं आजकल हर चीज का मजा ले रहा हूं। हर रोज गिरते तापमान का, बढ़ते प्रदूषण का, आम-ओ-खास की टेढ़ी चाल का, तलावार की तरह सीधे दोधारी चरित्रों का, मौके के मुताबिक चेहरे बदलने वालों के चेहरे के पीछे छिपे असली चेहरे को देखने और पढ़ने का, लुगदी साहित्य, अखबारों और खबरिया चैनलों में गढ़ी जा रही नई-नई अभिधाओं, लक्षणाओं तथा व्यंजनाओं का, उपमाओं का, बोलौवुड ट्पाइल में टांग पर टांग रखकर देश को सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक स्तर तथा पत्रकारिता की दशा और दिशा साबित करने के लिए एडिज में दिए जाने वाले कुतर्कों का, धर्म-मजहब या राष्ट्रवाद की आड़ में स्वाध सिद्धि के लिए दिए जा रहे कुतर्कों के पक्ष में कुतर्कों का, रुपये के गिरते मूल्य का और न जाने क्या-क्या। कोई एक चीज हो तो बताऊँ। पर अपना लोकचंद्र है न जी। जब तक फीताशाही में नहीं बदलता, तब तक कम से कम मजा तो लिया ही जा सकता है। मजा तो मैं अपना भी लेता हूं। सुबह उठ कर जब बिस्तर के सामने लगे आईने को देखता हूं तो सिसीफस की तरह जिंजीगी के बोझ को ढोने या स्यूपा पीटने के लिए ख़ुद के मंज लेते हुए दिन को नापने की तैयारी करता हूं।

दृष्टि कोण

कर्तव्य में एकता सुनिश्चित करती सेना की नैतिकता

कई बार ऐसे क्षण होते हैं जब अदालत का निर्णय किसी विवाद को निबटाने के अधिक बन जाता है, यह दिशा पथ करता है। अपने सैनिकों के साथ रॉजमेंटल पूजास्थल के भीतर जाने से इनकार करने वाले एक अधिकारी को सेवा मुक्त किए जाने के निर्णय को बरकरार रखने वाला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐसा ही एक क्षण है। यह उस सचवादी की पुष्टि करता है जो सैनिक सदा जीता है व जिसे लोकतंत्रों को निरंतर मजबूत करना चाहिए : एक गणराज्य अपने संस्थाओं के बूते खड़ा होता है और संस्थान अपना प्रण ईमानदारी से निभाने पर खड़े होते हैं। मजा तो मैं अपना भी लेता हूं। सुबह उठ कर जब बिस्तर के सामने लगे आईने को देखता हूं तो सिसीफस की तरह जिंजीगी के बोझ को ढोने या स्यूपा पीटने के लिए ख़ुद के मंज लेते हुए दिन को नापने की तैयारी करता हूं।

यह विवाद एक रॉजमेंट में उत्पन्न हुआ, जहां एक मंदिर और गुरुद्वारा साथ-साथ हैं और लंबे समय से एक एकीकृत सर्व धर्म स्थान के रूप में सुचारू हैं। अधिकारी ने यह कहकर अंदर जाने से इनकार कर दिया कि उसकी धार्मिक मान्यता उस पूजा स्थल के गंधारू में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। समूची सेना में, ऐसे स्थानों को मान्यता की दरकार नहीं है, बल्कि वे तो सह-अस्तित्व को पुष्ट करते हैं। उनका मतव्य केवल इतना कि विविधता के बीच, सम्बद्धता में दरार न आने पाए। परामर्श-सत्र और एक पादरी द्वारा यह आवश्यक किए जाने के बाद भी कि पूजा स्थल पर प्रवेश करना उसके धर्म से समझौता नहीं है, वह अधिकारी अपने रख पर अडिग रहा। विविधता में एकता का मतलब कभी भी इकाइयों के अंदर रार पैदा करना या किसी आदेश के मनमाफिक मायनों को प्रस्तुत करना नहीं रहा। सेना ने एकता का अर्थ कभी भी संख्या, अनुपात या निर्धारित संरचनाओं के रूप में नहीं लिया। जो कोई भी एक साथ खड़ा है, जहां कहीं से भी वो आता है और जिस भी

जए प्रावधानों के अनुसार एयरलाइन को लगभग 350 से 400 अतिरिक्त पायलटों की जरूरत थी, जबकि तैयारी बेहद सीमित थी

डॉ नीलम महेन्द्र
रोजाना देश के आसमान में लगभग 4,500 उड़ानें संचालित होती हैं। खास बात यह है कि इऽनमें से आधे से अधिक की कमान एक ही कंपनी ‘इंडिगो’ के हाथ में है। डीजीसीए के 2023–24 के आंकड़े बताते हैं कि इंडिगो का मार्केंट शेयर 65 प्रतिशत के आसपास है।यानी हर 100 यात्रियों में से लगभग 65 यात्री इंडिगो पर निर्भर हैं। किसी भी उद्योग में ऐसी स्थिति शायद ही देखने को मिले, जहां एक कंपनी पूरे बाजार की रीढ़ बन जाए। लेकिन जब रीढ़ ही कांपने लगे, तो पूरा शरीर हिल जाता है।हाल में यही हुआ जब डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नए नियम लागू किए। इनके अनुसार अब पायलटों को सात दिन काम के बाद 48 घंटों का आराम, लगातार दो रात से ज्यादा ड्यूटी नहीं, एवं दो नाइट लैंडिंग से अधिक नहीं जैसे नियम थे। इन नियमों का लक्ष्य साफ़ था—पायलटों की थकान कम करना और उड़ानों की सुरक्षा को नया मानक देना। दुनिया में थकान-जनित गलतियाँ एविएशन हादसों में लगभग 20–30 प्रतिशत योगदान देती हैं। भारत में, जहां हवाई यात्रा पिछले दस सालों में लगभग 70 प्रतिशत बढ़ी है, यह कदम देर से उठा एक महत्वपूर्ण सुधार था। लेकिन इसके कारण जिस प्रकार से इंडिगो की एक ही दिन में 1,000 उड़ानें देशभर में रह हुई और यात्री भारी परेशानी में पड़े, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि नियम बनाना पर्याप्त नहीं होता; जब तक उनका प्रभावी क्रियान्वयन न हो, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इंडिगो, जो भारत के घरेलू उड़ान बाजार पर लगभग एकाधिकार जैसा नियंत्रण रखती है, इन नियमों से सबसे अधिक प्रभावित हुई—या कहें कि उसकी अक्षमता से सबसे अधिक यात्री प्रभावित हुए। पर प्रावधानों के अनुसार एयरलाइन को लगभग 350 से 400 अतिरिक्त पायलटों की जरूरत थी, जबकि तैयारी बेहद सीमित थी। जब इस कमी की वास्तविक गूंज सामने आई, तब तक देर हो चुकी थी। इंडिगो को चार सौ से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। लेकिन इस अव्यवस्था की सबसे भारी कीमत किसने चुकाई? वे हजारों यात्री जिन्होंने रातों को हवाईअड्डों की ठंडी कुर्सियों पर गुजार दिया। वह माँ, जिसने छोटे बच्चे के साथ बिना किसी जानकारी के पूरी रात प्रतीक्षा की। वह बीमार पिता, जिसके पास उसका बेटा समय पर नहीं पहुँच सका। वह युवा, जो अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू से चूक गया। वह जाड़ा, जिसे अपनी ही शादी के रिसेप्शन में फ्लाइट रद्द होने के चलते ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। विडम्बना यह है कि भारत का यह एविएशन संकट न तो मशीनों की वजह से हुआ, न तकनीकी खराबी से, न मौसम से। यह संकट उस मॉडल की वजह से हुआ जिसमें सरकार भी

देश दुनिया से

क्या हमारा संविधान भारत को एक सूत्र में बांध रहा या बांट रहा?

हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह समय उपयुक्त होगा कि हम ईमानदारी से मूल्यंकम करें कि यह एकता और सामाजिक सद्भाव को विकसित करने में विफल क्यों रहा है। भारतीयों में एकता के अभाव के उदाहरण बहुत हैं.... हिंदू-मुस्लिम हिंसा, जाति-आधारित राजनीति, उत्तर-दक्षिण विभाजन, भाषाई विवाद, कश्मीर और पंजाब में अलगाववादी आंदोलन, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में सशस्त्र विद्रोह, मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा, इत्यादि। चूंकि इनमें से कई संघर्ष आजादी के बाद से जारी रहे हैं और कई नए हैं, इसलिए एक राजनीतिक दल या नेताओं के एक समूह को दोष देना मुश्किल है। इस तरह की व्यापक कलह भारत के शासन के तरीके में मूलतः समस्या की ओर इशारा करती है। हमारे संस्थापकों ने 1950 में संविधान को अपनाया, उन्हें उम्मीद थी कि यह देश को एक साथ रखने वाले गोंद के रूप में काम करेगा। उन्होंने दस्तावेज में उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई विशेषताओं को शामिल किया ...संसदिय निर्णयों के साथ बहुमत-शासन, एकीकृत देश के साथ राज्यों का संघ, धर्मान्पेक्ष संरक्षण के साथ धर्म की स्वतंत्रता, और राष्ट्रीय भाषा थोपे बिना क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता। संविधान की ये सभी तथाकथित एकीकृत विशेषताएं एकजुटता लाने में विफल रही हैं। बहुमत के शासन पर कोई संसदीय नियंत्रण नहीं है, केंद्र राज्यों पर हावी है, धर्मान्पेक्ष संरक्षण अर्थहीन हो गए हैं, और भाषाई लड़ाई जारी है। आइए इनमें से प्रत्येक कमी की जांच करें। अंतर्निहित बहुसंख्यकवाद बहुलवाद को नष्ट करता है : यह विचार कि संसद द्वारा बहुमत की सरकारों को नियंत्रित किया जाएगा, दो मुख्य कारणों से विफल रहा ..भारत की चुगलव्यू (इंटरव्यू) लिया था, न्यूज़ रूम में चीख-चीख कर खबर बेचने वाले चारणों का, नेताओं की दृघोर शंखिता का और उनके उंगली उठा-उठा कर तथा मुी बांध या भींच कर लगभग चीखते-चिल्लाते सम्बोधनों का, भक्तों द्वारा अपनी अंधभक्ति को सही साबित करने के लिए एडिज में दिए जाने वाले कुतर्कों का, धर्म-मजहब या राष्ट्रवाद की आड़ में स्वाध सिद्धि के लिए दिए जा रहे कुतर्कों के पक्ष में कुतर्कों का, रुपये के गिरते मूल्य का और न जाने क्या-क्या। कोई एक चीज हो तो बताऊँ। पर अपना लोकचंद्र है न जी। जब तक फीताशाही में नहीं बदलता, तब तक कम से कम मजा तो लिया ही जा सकता है। मजा तो मैं अपना भी लेता हूं। सुबह उठ कर जब बिस्तर के सामने लगे आईने को देखता हूं तो सिसीफस की तरह जिंजीगी के बोझ को ढोने या स्यूपा पीटने के लिए ख़ुद के मंज लेते हुए दिन को नापने की तैयारी करता हूं।

इसके परिणामस्वरूप एक खंडित

का आसमान इन दिनों जितनी तेजी और घनी उड़ानों से भरा हुआ है, उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। रोजाना देश के आसमान में लगभग 4,500 उड़ानें संचालित होती हैं। खास बात यह है कि इऽनमें से आधे से अधिक की कमान एक ही कंपनी ‘इंडिगो’ के हाथ में है। डीजीसीए के 2023–24 के आंकड़े बताते हैं कि इंडिगो का मार्केंट शेयर 65 प्रतिशत के आसपास है।यानी हर 100 यात्रियों में से लगभग 65 यात्री इंडिगो पर निर्भर हैं। किसी भी उद्योग में ऐसी स्थिति शायद ही देखने को मिले, जहां एक कंपनी पूरे बाजार की रीढ़ बन जाए। लेकिन जब रीढ़ ही कांपने लगे, तो पूरा शरीर हिल जाता है।हाल में यही हुआ जब डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नए नियम लागू किए। इनके अनुसार अब पायलटों को सात दिन काम के बाद 48 घंटों का आराम, लगातार दो रात से ज्यादा ड्यूटी नहीं, एवं दो नाइट लैंडिंग से अधिक नहीं जैसे नियम थे। इन नियमों का लक्ष्य साफ़ था—पायलटों की थकान कम करना और उड़ानों की सुरक्षा को नया मानक देना। दुनिया में थकान-जनित गलतियाँ एविएशन हादसों में लगभग 20–30 प्रतिशत योगदान देती हैं। भारत में, जहां हवाई यात्रा पिछले दस सालों में लगभग 70 प्रतिशत बढ़ी है, यह कदम देर से उठा एक महत्वपूर्ण सुधार था। लेकिन इसके कारण जिस प्रकार से इंडिगो की एक ही दिन में 1,000 उड़ानें देशभर में रह हुई और यात्री भारी परेशानी में पड़े, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि नियम बनाना पर्याप्त नहीं होता; जब तक उनका प्रभावी क्रियान्वयन न हो, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इंडिगो, जो भारत के घरेलू उड़ान बाजार पर लगभग एकाधिकार जैसा नियंत्रण रखती है, इन नियमों से सबसे अधिक प्रभावित हुई—या कहें कि उसकी अक्षमता से सबसे अधिक यात्री प्रभावित हुए। पर प्रावधानों के अनुसार एयरलाइन को लगभग 350 से 400 अतिरिक्त पायलटों की जरूरत थी, जबकि तैयारी बेहद सीमित थी। जब इस कमी की वास्तविक गूंज सामने आई, तब तक देर हो चुकी थी। इंडिगो को चार सौ से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। लेकिन इस अव्यवस्था की सबसे भारी कीमत किसने चुकाई? वे हजारों यात्री जिन्होंने रातों को हवाईअड्डों की ठंडी कुर्सियों पर गुजार दिया। वह माँ, जिसने छोटे बच्चे के साथ बिना किसी जानकारी के पूरी रात प्रतीक्षा की। वह बीमार पिता, जिसके पास उसका बेटा समय पर नहीं पहुँच सका। वह युवा, जो अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू से चूक गया। वह जाड़ा, जिसे अपनी ही शादी के रिसेप्शन में फ्लाइट रद्द होने के चलते ऑनलाइन शामिल होना पड़ा। विडम्बना यह है कि भारत का यह एविएशन संकट न तो मशीनों की वजह से हुआ, न तकनीकी खराबी से, न मौसम से। यह संकट उस मॉडल की वजह से हुआ जिसमें सरकार भी

संघर्ष... तमिल, सिख, कश्मीरी और नागा .. आज भी जारी हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह केवल तेज होता गया, अंततः बिहार, झारखंड और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। 2010 में, सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता ने कहा कि ‘‘1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारत द्वारा लड़े गए पांच युद्धों की तुलना में आंतरिक असुरक्षा के कारण अधिक लोगों की जान गई है।’’

सतही धर्मान्पेक्षता धार्मिक विभाजन को भड़काती है : धर्मान्पेक्षता भारतीय संविधान का एक और स्तंभ है जो सैद्धांतिक रूप में महान प्रतीत होता है लेकिन निष्पादन में टुटिपूरी है। संविधान धर्म को स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। परंतु भारत में धर्मान्पेक्षता ‘धर्म और सरकार के बीच सख्त अलगाव’ पर आधारित नहीं, बल्कि ‘सभी धर्मों के लिए समान सम्मान’ पर आधारित है। व्यवहार में, इसने सरकार को धार्मिक मामलों में मनमानी से हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है। इस असमान दृष्टिकोण ने ‘तुट्टीकरण’ और ‘बहुसंख्यकवाद’ दोनों आरोपों को जन्म दिया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सत्ता में कौन है। इस प्रकार की धर्मान्पेक्षता ने धार्मिक पहचान को बेअसर करने के बजाय, अक्सर इसका राजनीतिकरण किया है। चुनावी प्रसिद्धा सहियों गुरानी धर्मान्पेक्ष संस्कृति को खोने का जोखिम उठा रहा है। कई भारतीय विचारक अभी भी मानते हैं कि भारत की धर्मान्पेक्षता जीवित रह सकती है यदि सरकारें सभी धर्मों से ‘सैद्धांतिक दूरी’ बनाए रखें, या उन्हें समान रूप से बढ़ावा दें। लेकिन वे राजनेताओं को नहीं पहचानते और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। भाषाई विभाजन : भाषा हमेशा भारतीयों में अलग पहचान का एक परिभाषित मार्कर रही है, और संविधान द्वारा इसे संभालना लगातार तनाव का स्रोत रहा है। निर्माताओं ने हिंदी और अंग्रेजी को ‘आधिकारिक भाषाओं’ के रूप में नामित करते हुए किसी भी एक राष्ट्रीय भाषा को घोषित करने से परहेज किया।

निर्णय

खोलने या पुन: व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सकता। कर्तव्य निर्वहन से इंकार को समझना चाहिए, न कि पुन: रूपरेखा में बदल रही है। और जो भी नैतिकता विशेष की पुन: व्याख्या में लगते दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही वे इसके वर्ण, वर्णमाला और व्याकरण से अनभिज्ञ हैं। सेना की प्रथाएं युद्ध की वास्तविकताओं, सामंजस्य की दरकार और विविधतापूर्ण इकाइयों द्वारा एकीकृत होकर लड़ने वाले अनुभूत अस्पृश्य से ढाली गई हैं। कुछ लोग पृष्ठ सकते हैं कि अगर उक्त अधिकारी बहुसंख्यक समुदाय से होता, तब क्या प्रतिक्रिया अलग होती। यह सवाल फौजी वर्दी को गलत तरीके से पढ़ता है। सेना पहचान को अधिमान नहीं देती; सप्लिव पर जोर देती है। एकता जनित कर्तव्य का उल्लंघन एक समान है, चाहे वह कोई भी करे। नैतिकता किसी एक या कई के लिए, अल्पसंख्यक से हो या बहुसंख्यक वर्ग से, सख्त के लिए समान है, क्योंकि जिस घड़ी पहचान में गणित प्रवेश करता है, उसी पल सामंजस्य का निकास हो जाता है।

जबकि तैयारी बेहद सीमित थी

इंडिगो: अव्यवस्था का असली जिम्मेदार कौन?

निश्चित रही, नियामक भी आत्म-संतोष में रहा, और एयरलाइन भी अपनी क्षमता के भ्रम में। तीनों की इस सामूहिक नौद ने पूरे देश की नौद उड़ा दी। इंडिगो ने डीजीसीए के समक्ष आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि यह संकट ‘मिसजनमेंट और प्लानिंग की विफलता’ का परिणाम था।यानी कंपनी ने अपनी ही सामर्थ्य का गलत आकलन किया, FDTL के दूसरे चरण का क्रियान्वयन संभाल नहीं पाई, और उसके परिणाम अब राष्ट्र भर में दिखाई दे रहे हैं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिगो ने कहा है कि वह फरवरी 2026 तक पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाएगी। इंडिगो की इस विफलता ने सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि पूरे एविएशन बाजार को झकझोर दिया।जिस दिन इंडिगो डगमगाई, उसी दिन लगभग सभी प्रमुख रूट्स पर किराए 25–40 प्रतिशत तक उछल गए।दिल्ली—मुंबई जैसे रूट पर किराया 25,000 रुपये से ऊपर पहुंच गया।विडम्बना यह कि जो एयरलाइन चार दिनों में 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर अराजकता पैदा कर रही थी, वही यात्रियों से तीन से छह गुना तक किराये वसूल रही थी। इस संकट को और गहरा बनाया राजधानी दिल्ली के हॉटलों में 95 प्रतिशत ऑक्युपेंसी और अचानक बढ़ी मांग ने, जिसने दरों को कुंड़ा गुना ऊपर पहुंचा दिया। अब मूल प्रश्न यह उठता है—क्या इंडिगो को इस अव्यवस्था का पूर्वानुमान नहीं था?

क्योंकि डीजीसीए के नए नियम जनवरी 2024 में ही घोषित कर दिए गए थे। उन्हें जून 2024 से लागू करना था, पर उद्योग ने तैयारी की दिक्कत बताई।सरकार ने उदारता दिखाकर समय बढ़ाया—जुलाई 2025 तक। फिर कंपनियों के अपभार पर अंतिम तारीख बढ़कर 1 नवंबर 2025 कर दी गई। इतना समय मिलने के बाद भी यदि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस तरह ढह जाय, तो प्रश्न सिर्फ इंडिगो पर नहीं, सरकार और नियामकों पर भी उठेगे। यह कैसी नीति-निर्माण प्रक्रिया थी जिसमें समय तो दिया गया, पर तैयारी की जाँच नहीं हुई? स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार को अंततः अपने ही नियमों पर रोक लगानी पड़ी—यही इस संकट का सबसे चिंताजनक पहलू है। और यहाँ एक और असहज प्रश्न खड़ा होता है यदि एक कंपनी पूरे देश और सरकार को इस हद तक हिला सकती है कि आधी उड़ानें प्रभावित हो जाएँ, तो क्या सरकार को अपने निर्णयों की विश्वसनीयता, प्रभाव और क्रियान्वयन की सुनिश्चितता पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? यह प्रश्न सरकार की नीयत पर नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और नियामक प्रक्रिया की मजबूती पर उठाया जाना चाहिए। आज देश उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ कोई भी पक्ष निर्दोष नहीं उहराया जा सकता—

न सरकार, जो एकाधिकार-जैसी स्थिति बनने से रोकने में विफल रही; न इंडिगो, जिसने अपनी क्षमता का अनुमान बेहद गलत लगाया; न नियामक, जिसने यह मान लिया कि कागज पर बने नियम जमीन पर भी उसी सहजता से लागू हो जाएंगे।

सरकार जब छोटे शहरों की कर्नेक्टिविटी, किफायती उड़ानें और “हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा” की बात करती है, तो यह संकट सिर्फ इंडिगो का नहीं—देश की उड़ान का संकट बन जाता है। विमान इंडिगो के थे, पर रुकावट भारत की उड़ान में आई। भविष्य में देश की उड़ान कभी न थके—इसके लिए आवश्यक है कि सरकार ने केवल नियम बनाए, बल्कि उनके क्रियान्वयन की वास्तविकता और उद्योग की क्षमता को भी गंभीरता से समझें। ऐसे ठोस कदम उठाए जाएँ कि भविष्य में कोई भी एयरलाइन इस प्रकार की अव्यवस्था को “अनुमान की गलती” कहकर अपना दायित्व न टाल सके।

यह सुखद ही है कि कृतज्ञ राष्ट्र देश के स्वतंत्रता सेनानियों में ओज का संचरण करने वाले गीत वंदे मातरम के सृजन के डेढ़ सौ साल पूरे होने को एक उत्सव की तरह मना रहा है। स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत करोड़ों भारतीयों में इस गीत ने आजादी का जन्मा भरा था। लाखों स्वतंत्रता सेनानी इस गीत से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर हो जाते थे। इस पावन वेला में देश के विभिन्न भागों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सही मायनों में यह अवसर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का भी है। इस गीत की सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की दृष्टि से देखा था। इसी आलोक में वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर लोकसभा में इस पर चर्चा का शुरू होना सुखद ही है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब इस गीत के सृजन के पचास साल पूरे हुए तो देश परतंत्र था। जब इसके सौ साल पूरे हुए तो देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, फलतः उस दौर में इस गीत को जनता व स्वतंत्रता सेनानियों का सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला। निस्संदेह, बंकिम चंद्र चटर्जी की इस रचना ने बंगाल में क्रांतिकारियों को गहरे तक प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि, विपक्ष इसे सुखियों में लाने के फैसले के

राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा है। वे इसके समय को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि में जन्मे इस ओज के गीत को बंगाली समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़कर देखा। खासकर बंगाल विभाजन के बाद इसे बंगाल की एकिकता पर फिरगियों के प्रहार के दौर में एक महरम के तौर पर देखा। निस्संदेह, देश ऐसे स्मरण उत्सव का हकदार है, मगर वे चुनावी नजरियों से मुक्त हों। विपक्ष की दलील है कि जब पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण सर्वस्वीकार्यता का आलम ये था कि भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में महात्मा तर्क गढ़े जा रहे हैं। संसद में प्रधानमंत्री के गांधी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की संबोधन में वंदे मातरम को एकता के सूत्रधार दृष्टि से देखा था। इसी आलोक में वंदे के रूप में सराहा गया। लेकिन इसके मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर राजनीतिक निहितार्थों पर भी चर्चा हुई। लोकसभा में इस पर चर्चा का शुरू होना सुखद ही है। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जब इस गीत के सृजन के पचास साल पूरे हुए तो देश परतंत्र था। जब इसके सौ साल पूरे हुए तो देश निशाने पर लिया। विपक्षी दलील है कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान करने की कवायद में वैचारिक विभाजन को हवा दी जा रही है। कहा गया कि पश्चिम बंगाल, जहां इस गीत का जन्म हुआ, वहां की सांस्कृतिक पहचान राजनीति से जुड़ी रही है। वंदे मातरम एक भावनात्मक प्रतीक है और इसीलिए एक और स्वतंत्रता संग्राम को गति देने में नाराजगी राजग सरकार की उस प्रवृत्ति को ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हालांकि, लेकर है जिसमें वह सांस्कृतिक प्रतीकों को विपक्ष इसे सुखियों में लाने के फैसले के निहितार्थों में बदल रही है। उन्हें राजनीतिक निहितार्थों की बात कर रहा आशंका है कि साझी विरासत पर चिंतन के है।वे इसके समय को लेकर प्रश्न उठा लिये आयोजित विमर्श का उपयोग चुनावी रहे हैं। अविभाजित बंगाल की पृष्ठभूमि में लाभ अर्जित करने के लिये किए जाने का जन्मे इस ओज के गीत को बंगाली समाज अपनी जड़ें जमाए हुए है, फिर भी उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा का ममता बनर्जी द्वारा समर्थन किया जाना दर्शाता है कि वह इस मुद्दे को छोड़ने का इरादा नहीं रखती है। विडंबना ही है कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में ओज भरने वाले गीत के विमर्श में चिंतन की गंभीरता प्रभावित हुई है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल आज बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक हिंसा से जूझ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि हमारा सांस्कृतिक गौरव आवश्यक है, लेकिन यह सुशासन का विकल्प नहीं हो सकता। इस ओज के गीत के 150 साल पूरे होने पर, इसे एकता को मजबूत करने और राष्ट्रवाद को बहुलता से स्वीकार करने के अवसर के रूप में होना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय, इस बहस के ध्रुवीकृत माहौल में बदलने के विवाद के पैदा होने की चिंता है। सही मायनों में देश के नेतृत्व का इतिहास का उपयोग राष्ट्र को एकजुट करने वाला होना चाहिए।





जापान में पहले भीषण भूकंप आया, अब तेज झटकों से फैली दहशत, अलर्ट जारी

टोक्यो, 09 दिसंबर (एजेंसियां) ।

उत्तरी जापान में सोमवार देर रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 23 लोग घायल हो गए और प्रशांत तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। अधिकारियों ने संभावित झटकों और महाभूकंप के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है। यह भूकंप रात लगभग 11:15 बजे प्रशांत महासागर में, जापान के मुख्य द्वीपों के सबसे उत्तरी प्रान्त, आओमोरी के तट से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) दूर आया था। भूकंप के बाद लगातार आ रहे

आपटरशॉक्स की वजह से लोग दहशत में हैं। जापानी सरकार अभी भी सुनामी और देर रात आए भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने आने वाले दिनों में संभावित झटकों के बारे में चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने कहा कि टोक्यो के पूर्व में बिबा से लेकर होक्काइडो तक जापान के उत्तरपूर्वी तट पर 8 तीव्रता के भूकंप और संभावित सुनामी का खतरा थोड़ा बढ़ गया है। एजेंसी ने क्षेत्र की 182 नगर पालिकाओं के निवासियों से आने वाले सप्ताह में अपनी आपातकालीन तैयारियों पर

नज़र रखने का आग्रह किया है। एजेंसी के भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रभाग के अधिकारी सातोशी हरादा ने कहा, आपकों तैयार रहने की ज़रूरत है, यह मानते हुए कि ऐसी आपदा फिर से हो सकती है। स्थानीय नागरिक, सुविधा स्टोर के मालिक नोबुओ यामादा ने बताया, मैंने पहले कभी इतने बड़े भूकंप का अनुभव नहीं किया, सीभाग्य से हमारा क्षेत्र में बिजली को लाइनें अभी भी चालू थीं। वहीं, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि आओमोरी के दक्षिण में इवाते प्रान्त के कुजी बंदरगाह में 70

सेंटीमीटर (2 फीट, 4 इंच) तक की सुनामी मापी गई और क्षेत्र के अन्य तटीय समुदायों में 50 सेंटीमीटर तक की सुनामी आई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार तड़के होन्चो से लगभग 122 किलोमीटर (76 मील) दक्षिण में, 35 किलोमीटर की गहराई पर, 5.1 तीव्रता के भूकंप का केंद्र जमीन से 30 किमी की गहराई पर था। इससे पहले सोमवार को दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहले सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर 3.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 80 किमी की गहराई पर था। इसके बाद दोपहर 3 बजकर 46 मिनट पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी की गहराई पर था। उल्लेखनीय है कि म्यांमार चार टेक्टोनिक प्लेटों (भारतीय, यूरेशियन, सुंडा, बर्मा) के बीच स्थित होने के कारण भूकंप और सुनामी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

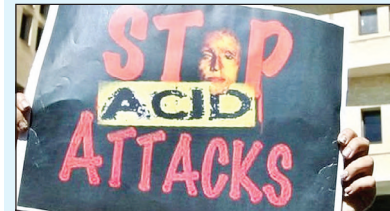
न्यूज़ ब्रीफ

म्यांमार में 3.7 तीव्रता का भूकंप



नेपीडॉ (म्यांमार)। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सोमवार-मंगलवार की मध्य रात्रि को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के मुताबिक, 09 दिसंबर 2025 को म्यांमार में मध्य रात्रि एक बजकर 21 मिनट (भारतीय समयानुसार) पर 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से 30 किमी की गहराई पर था। इससे पहले सोमवार को दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पहले सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर 3.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 80 किमी की गहराई पर था। इसके बाद दोपहर 3 बजकर 46 मिनट पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किमी की गहराई पर था। उल्लेखनीय है कि म्यांमार चार टेक्टोनिक प्लेटों (भारतीय, यूरेशियन, सुंडा, बर्मा) के बीच स्थित होने के कारण भूकंप और सुनामी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

एसिड अटैक एक गंभीर और जल्वत समस्या.....भारत सहित कई देशों में महिलाएं हो रही प्रभावित



कोलंबिया। दुनिया में एसिड अटैक एक गंभीर और जल्वत समस्या है। भारत, यूके, बांग्लादेश, युगांडा और कोलंबिया इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं। महिलाओं पर हमले अधिक होते हैं। कानून को कड़े करने और समाज की सोच बदलने और पीड़ितों के सुरक्षा उपाय अपनाने की जरूरत है। एसिड अटैक ऐसा अपराध है जो किसी भी देश, किसी भी समाज की तस्वीर बिगाड़ देता है, यह न सिर्फ चेहरे को जलाता है, बल्कि जिंदगी भर का घाव देता है। रिपोर्ट यह बताती है कि दुनिया के कई देशों में यह समस्या किन्ती बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पांच देश हैं, जहां एसिड अटैक के मामले सबसे ज्यादा दर्ज हुए हैं। युनाइटेड किंगडम में 2022 में 710 मामले दर्ज हुए। भारत में हर साल करीब 614 मामले होने का अनुमान है। बांग्लादेश में 2002 में 400 मामले दर्ज किए गए थे, जो उस समय वहां की सबसे बड़ी संख्या थी। युगांडा में 1985 से 2011 के बीच 382 मामले दर्ज हुए। कोलंबिया में हर साल लगभग 100 मामले दर्ज होते हैं। बात दें कि भारत में 2018 में आधिकारिक तौर पर 228 मामले दर्ज हुए थे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि असल संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। यहां ज्यादातर पीड़ित महिलाएं और लड़कियां होती हैं। इसमें से भी कई मामले घर-परिवार, रिश्तेदारी या समाजिक विवादों से जुड़े होते हैं। वहीं बांग्लादेश में 2002 के आसपास एक पहुंच अटैक के मामले सबसे ज्यादा यानी 400 तक पहुंच गए थे। यहां एक अध्ययन में बताया गया कि 80 प्रतिशत एसिड हमले पीड़ितों के घर के भीतर ही होते हैं। यानी अपराधी अवसर परिचित होते हैं। करीब 70 प्रतिशत पीड़ित महिलाएं और लड़कियां होती हैं। शुरुआत में हालात बहुत खराब थे लेकिन कड़े कानूनों और जागरूकता से धीरे-धीरे मामलों में कमी आई। वहीं यूके में एसिड अटैक के मामले दुनिया में सबसे अधिक होते हैं। 2017 में यह संख्या 941 तक पहुंच गई थी। इसके बाद सरकार ने कानून कड़े हुए, इतनी ही नहीं जागरूकता बढ़ी और 2021 में संख्या घटकर 421 रह गई। लेकिन 2022 में हमलों में फिर से उछाल दिखाई दिया और 710 मामले सामने आए।

छोटी बातलों में आसू भर कर बेचती है महिला, कमती है लाखों रुपए

वाशिंगटन। अमेरिका में एक महिला ऐसी है, जो हर वक्त रोती है। महिला किसी दुख की वजह से नहीं रोती है, सह उस महिला का अनोखा पेशा।। रोते समय निकलने वाले आसूओं को यह महिला कांच की छोटी बातलों में भरकर बेचती है। महिला को एक बातल आसूओं के लिए उसे करीब 52 हजार रुपये मिलते हैं। यह काम न सिर्फ उसे आर्थिक तौर पर मजबूत बना रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी कहानी को लेकर भारी चर्चा भी हो रही है। अमेरिका के मिडवेस्ट में रहने वाली 44 वर्षीय चार बच्चों की मां लिज रिबर इन दिनों चर्चा में हैं। लिज पेशे से एक कटेंट क्रिएटर हैं और 21 साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। उन्होंने खुलासा किया कि दिसंबर का महीना उनके लिए सबसे ज्यादा ख़रत रहता है क्योंकि इसी दौरान वह सबसे ज्यादा रोती हैं, लेकिन यह रोना मजबूरी में नहीं, बल्कि 'वर्क मोड' में होता है। उनके पास कांच के छोटे जार पहले से तैयार रहते हैं जिन्हमें वे अपने आसू इकट्ठा करती हैं और बाद में इन्हें अपने प्रशंसकों को बेच देती हैं।

मोदी-पुतिन की दोस्ती से चिढ़े ट्रंप, भारत पर लगा सकते हैं एक और टैरिफ, दिए संकेत

वाशिंगटन, 09 दिसंबर (एजेंसियां) ।

हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया के कई देशों की नज़रें लगीं हुई हैं। अमेरिका एक एक कदम पर नज़र बनाए हुए था। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही भारत पर एक और टैरिफ लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब भारत से आयात होने वाले चावल पर टैरिफ बढ़ा सकता है। साथ ही वह कनाडा से आयातित उर्वरक पर भी टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी उत्पादकों ने डोनाल्ड ट्रंप से मार्केट में सस्ते विदेशी चावल की शिकायत की है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था। वहीं दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक इस सप्ताह एक बार फिर शुरू होने वाली हैं। 10 और 11 दिसंबर को अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेगा और द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का प्रयास करेगा। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार होंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर का बेलाउट पैकेज जारी किया है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जांच करेगी कि अमेरिकी की मार्केट में सस्ता विदेशी चावल कितना आ रहा है। किसानों ने डोनाल्ड ट्रंप पर कड़े कदम उठाने का दबाव बनाने की कोशिश की। किसानों ने कहा कि चावल के विदेशी आयात पर सब्सिडी की वजह से घरेलू चावल को सही कीमत नहीं मिल पाती है। इसपर ट्रंप ने कहा कि वे लोग धोखा दे रहे हैं और उनपर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अब वह कनाडा के उर्वरक पर भी टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। लूसियाना के केनेडी राइस मिल के सीईओ मैरिल केनेडी ने ट्रंप से कहा कि भारत, थाइलैंड और चीन से सबसे ज्यादा चावल आ रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों पर टैरिफ लगा है लेकिन चावल पर टैरिफ दोगुना करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि उनपर और ज्यादा टैरिफ लगाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से उन देशों की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया जो कि अमेरिका में ज्यादा टैरिफ निर्यात कर रहे हैं। केनेडी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। वट्रूप ने फिर बेसेंट की ओर देखते हुए कहा, 'भारत, मुझे भारत के बारे में बताइए। भारत को ऐसा करने की अनुमति



दुनिया भर में 'रमका राजा' की पहचान बनाए हुए है बकाई रम

लंदन। शराब के शीकियों के लिए बकाई रम अपनी अनोखी गुणवत्ता, नवाचार और मजबूत ब्रांड पहचान की वजह से वैश्विक स्तर पर 'रम का राजा' की अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है। बकाई रम की शुरुआत बेहद साधारण थी। यह सफ़र डेमिनिकन गणराज्य की एक छोटी सी डिस्टिलरी से शुरू होकर वैश्विक ब्रांड बनने तक पहुंचा। बकाई के इस शानदार विकास के पीछे उसकी बेहतरीन क्वालिटी, अनोखी डिस्टिलेशन तकनीक और असाधारण मार्केटिंग रणनीति को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। इस रम को पीना आसान माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद बेहद स्मूथ, संतुलित और सुखद होता है। यही कारण है कि बकाई रम आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम रमों में शुमार है और 200 से अधिक देशों में इसकी बिक्री होती है। इस महशूर ब्रांड की स्थापना 1862 में वयुबा में डॉन फेकुडो बकाई ने की थी, जो मूल रूप से स्पेनिश-यहूदी मूल के व्यवसायी थे। उन्होंने रम बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया में सुधार किया और एक नई तकनीक विकसित की, जिसने रम को कड़क और तीखी पेय से बदल कर एक स्मूथ और बेहद स्वादिष्ट ड्रिंक में बदल कर दिया। इस बदलाव ने बाजार में बकाई रम को अलग पहचान दी और धीरे-धीरे इसका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगा।

क्यों हैं उन्हें शुल्क देना होगा। क्या उन्हें चावल पर छूट मिली हुई है' इस पर बेसेंट ने कहा, नहीं सर, हम अभी उनके साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।

केनेडी ने ट्रंप को यह भी बताया कि भारत के खिलाफ वश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में एक मामला चल रहा है। उन्होंने कहा, यह उन देशों पर शुल्क लगाकर बहुत जल्दी हल हो जाएगा, जो अवैध रूप से सामान भेज रहे हैं। आपकी समस्या एक दिन में हल हो

जाएगी इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीतना है। आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और वैश्विक बाजार में 28 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। वह शीर्ष निर्यातक भी है, जिसकी 2024-25 में वैश्विक निर्यात में 30.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। भारत चावल की जो किस्में वैश्विक स्तर पर निर्यात करता है, उनमें सोना मसूरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में पसंद की जाती है।

कांगो के राष्ट्रपति ने रवांडा पर शांति समझौते के उल्लंघन का लगाया आरोप

किशासा, 09 दिसंबर (एजेंसियां) ।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने सोमवार को रवांडा पर हाल ही में हुए शांति समझौते का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ ही दिन पहले त्सिसेकेदी ने वाशिंगटन में एक समारोह में भाग लेकर उन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनका उद्देश्य कांगो के खनिज-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में चल रहे वर्षों पुराने संघर्ष को समाप्त करना था। राष्ट्रपति ने यह बयान संसद को संबोधित करते हुए दिया। रवांडा की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एम23 की बढ़ती गतिविधियों ने बहाई तनावपूर्ण स्थिति अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में पिछले महीनों में कांगो, रवांडा और एम23 विद्रोही ग्रुप के बीच कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बावजूद क्षेत्र में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सप्ताहों में रवांडा समर्थित बचाए जा रहे एम23 विद्रोहियों ने बुरुंडी सीमा के पास स्थित लुवुंगी गांव पर कब्जा कर लिया। दो स्थानीय निवासियों ने स्थानीय मीडिया से इसकी पुष्टि की और विद्रोहियों की बैठक का एक वीडियो भी साझा किया। हालांकि, रवांडा इन विद्रोहियों को समर्थन देने से लगातार इनकार करता रहा है। 36 लोगों की मौत, स्थिति और बिगड़ने की आशंका स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, लुवुंगी से पीछे हटते कुछ कांगोली



सैनिकों की पास के शहर सांगे में स्थानीय वाजालेंदो रक्षा बलों के साथ झड़प हो गयी। रविवार को सांगे में बमबारी या ग्रेनेड हमले की रिपोर्ट मिली, जिसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई। एक नागरिक संगठन द्वारा साझा की गई तस्वीरों में रंगीन गैर-सैन्य कपड़ों में खून से लथपथ कई शव दिखे। इनमें दो बच्चे भी शामिल बताए गए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किस पक्ष ने किया और किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल हुआ।

कांगो की सेना और एम23 दोनों ने इस मामले

पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है।

समझौते के बावजूद बढ़ रहा अविश्वास.....

पिछले सप्ताह दोनों देशों कांगो और रवांडा ने जून में किए गए अमेरिका-समर्थित शांति समझौते को दोहराया था और वाशिंगटन में नए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसके बावजूद ताजा घटनाओं ने क्षेत्र में स्थिरता लाने के प्रयासों पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। पूर्वी कांगो में लंबे समय से जारी संघर्ष और ताजा हिंसा से यह स्पष्ट है कि शांति प्रक्रिया अब भी बेहद नाजुक स्थिति में है।

चीन को मिली कामयाबी: समुद्र के खारे पानी से बना दिया पेट्रोल का बेहतर विकल्प

बीजिंग, 09 दिसंबर (एजेंसियां) ।

वैश्विक स्तर पर पीने योग्य पानी की भारी कमी और पेट्रोल-डीजल के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प की खोज जारी है। ऐसे में चीन ने एक अनोखी उपलब्धि हासिल कर दुनिया को चौंका दिया है। पूर्वी प्रांत शेडोंग के रिझाओ शहर में स्थापित दुनिया की पहली ऐसी फैक्ट्री ने समुद्री खारे पानी को न केवल पीने लायक मीठा बनाया है, बल्कि भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार कर लिया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी लागत मात्र 2 युआन यानी लगभग 24 भारतीय रुपये प्रति क्यूबिक मीटर है। यह तकनीक इतनी किफायती है कि सकुदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ चुकी है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह सुविधा पूरी तरह से समुद्री जल और निकटवर्ती स्टील तथा पेट्रोकेमिकल कारखानों से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर है। बर्बाद हो रही गर्मी



का अब उत्पादक उपयोग हो रहा है। प्रणाली 'एक इनपुट, तीन आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनपुट के रूप में समुद्री जल और अपशिष्ट

ऊष्मा ली जाती है, जबकि तीन प्रमुख उत्पाद प्राप्त होते हैं।

पहला उत्पाद है अल्ट्रा-शुद्ध मीठा पानी।

प्रतिवर्ष 800 टन समुद्री जल प्रसंस्करण से 450 क्यूबिक मीटर उच्च गुणवत्ता वाला पानी मिलता है, जो पीने और औद्योगिक उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त है। दूसरा उत्पाद ग्रीन हाइड्रोजन है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,92,000 क्यूबिक मीटर है। तीसरा उत्पाद ब्राइन है, जिसमें 350 टन खनिज युक्त अवशेष बचता है, जिसका उपयोग समुद्री रसायनों के निर्माण में होता है।

लागत की दृष्टि से यह प्लांट विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है। चीन में उत्पादित पानी की कीमत 24 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि सऊदी अरब और यूएई में सबसे सस्ता डिसेलिनेटेड पानी 42 रुपये में उपलब्ध है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सबसे बड़े प्लांट में लागत 186 रुपये तक पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह है कि बीजिंग में घरेलू नल का पानी 5 युआन प्रति क्यूबिक मीटर पड़ता है, जबकि समुद्री जल से प्राप्त पानी उससे आधे से भी कम में तैयार हो रहा है। हाइड्रोजन को पेट्रोल का 'बाप' कहा जाता है

क्योंकि यह पूर्णतः प्रदूषण-मुक्त ईंधन है। परंपरागत रूप से इसके उत्पादन में भारी बिजली और शुद्ध मीठे पानी की आवश्यकता होती थी। समुद्री जल मशीनों को क्षति पहुंचाता था। लेकिन रिझाओ की यह तकनीक श्वारे पानी से हाइड्रोजन बना रही है। उत्पादित हाइड्रोजन इतनी मात्रा में है कि 100 बसें प्रतिवर्ष 3,800 किलोमीटर तक चल सकती हैं। लाओशांन लेबोरेटरी के वरिष्ठ इंजीनियर किन जियांगगुआंग ने कहा, यह केवल सिलेंडर भरने की प्रक्रिया नहीं है; यह समुद्र से ऊर्जा निकालने का नया मार्ग है।

समुद्री जल में मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोड पर जमा होकर मशीनों को खराब कर देते थे। लेकिन पिछले तीन सालों से यह प्लांट बिना किसी रुकावट के निरंतर कार्यरत है, जिससे जंग की समस्या का स्थायी समाधान सिद्ध हो चुका है। यह नवाचार उन देशों के लिए वरदान है जहां समुद्र तो उपलब्ध है, किंतु मीठा पानी और ऊर्जा संसाधन सीमित हैं।

पूताना, जोएसडब्ल्यू वर्तमान हाँकी क्लब, श्राची राह बंगाल टाइटान्स (वर्तमान चैंपियन), वेदाता कलिंग लॉयड्स, रांची रायल्स, एसजी पाइराट्स और एचआईएल गर्वनिंग काउंसिल खिला साँगे। पुरुष लीग में ३३ मैच खेले जाँगें, जिनमें अर्जेंटीना, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे शीर्ष हाँकी राष्ट्रों के खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी टीमों में सिंगल राउंड-राफिन प्रारूप में एक-दूसरे से खेलेंगी। शीर्ष चार टीमों में प्लेऑफ में पहुँचेंगी।

स्वाधिकाफायर । और एलिमिनेटर २३ जनवरी (मध्याह्नश्चर) को खेला जाँगा।

भूमिकाएं दी गयी हैं। उससे टीम का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। ऐसे में अब वह टीम में अंकित बदलाव की जरूरत नहीं समझते हैं। पाक टीम ने इस साल पेशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम से मिली हार के बाद अब्दुल समद, बाबर आज़म, उस्मान खान और नसीम शाह को टीम में शामिल किया था। जिसके बाद से ही उसका प्रदर्शन सुधरा है। पाक टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया वही। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ हुई त्रिकोणीय सीरीज जीती। इसी से उस्तादित होकर मानान ने कहा, 'मुझे विश्व कप से पहले टीम में अंकित बदलाव की जरूरत नहीं लगती है। हमारा मौजूद संयोजन विश्व कप में भी बना रहेगा। पिछले मौजूद हार खिलाड़ी को कुछ विशिष्ट भूमिका दी गई जिससे टीम का प्रदर्शन बेहतर हुआ। गौरतलब है कि पाक की विश्व कप से पहले छह टी20 मैच खेले हैं। विश्व कप अगले साल साल फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसमें पाक टीम के सभी मुक़ाबले कोलोंग में होंगे। आगे ने कहा कि मैचों की सीमित संख्या के कारण बड़े बदलाव करना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, 'विश्व कप से पहले हमें छह टी20 मैच खेले हैं और इससे हमें बदलाव की जगह पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने पर विचार करना होगा।

हादिक पंड्या ने इस मैच में 28 गेंदों पर 59 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छके जड़े।बेल्बाजी के बाद गेंदबाजों में भी हादिक पंड्या ने कामाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया। इस मैच में उन्होंने दो बड़े रिकार्ड भी बनाए। पहला उन्होंने इस मुकामले के दौरान अपने 100 टी20 इंटरनेशनल छके पूरे किए और इसके बाद गेंदबाजों के समय उन्होंने 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट भी पूरा किया। हादिक के अलावा गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षय पटेल ने दो-दो विकेट झटके। जिससे कारण टीम इंडिया ने आसानी से मैच जीता।

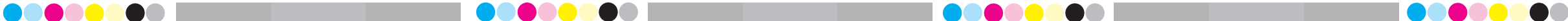
हांगकांग में डब्ल्यूटीटी फाइनल्स हांगकांग के लिए ड्रॉ निकाले जाने के अवसर पर एकसाथ नजर आये खिलाड़ी।

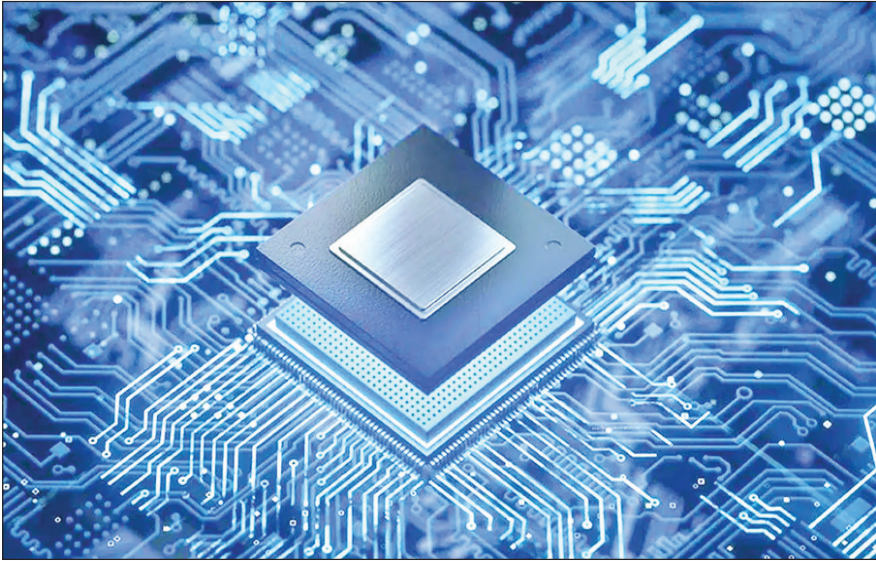
दूसरी ओर, पेट कमिस के लिए सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। उन्हें बुधवार को घोषित होने वाली 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है और वह एक बार फिर स्टीवलिंघ से कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। कमिस ने जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान पीठ में दर्द महसूस करने के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन उनकी रिकवरी उम्मीद से तेज रही है।

मैकडोनाल्ड ने बताया कि कमिस ने

स्टेच के लिए चुनी गई 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है।

मिचेल है और नए गेंदबाजों को लेकर डेड कोच राब वॉल्टर ने एक बयान में कहा, 'मिच एक युवा खिलाड़ी है जिन्होंने पहले ही व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अच्छी भूमिका निभाई है।' कैटबरी के लिए उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी बेहतर नहीं रहा है। टेस्ट टीम में उनका उमर आना उनके कैरियर का खास पल है और हम उन्हीं खेतों देखने को लेकर काफी उत्साहित हैं।' 'क्रिस्टियन क्लार्क और माइकल ने पर बात करते हुए वॉल्टर ने कहा, 'दोनों खिलाड़ी लंबे समय से हमारी नजर में हैं और फोर्लु क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।' क्लार्क ने नॉर्दन इंडियन ट्रस्ट के लिए 28 मैचों में 79 विकेट लिए हैं, जबकि माइकल ने के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 70 मैचों में 208 विकेट हैं।' दोनों के पास रेड-बॉल क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं कौशल है और यह उनके लिए उच्च स्तर पर खुद को साबित करने का शानदार मौका है।





भारत बनेगा चिप मैनुफैक्चरिंग हब : इंटेल-टाटा की साझेदारी से सेमीकंडक्टर क्रांति तेज

1.18 लाख करोड़ निवेश से गुजरात और असम में तैयार होंगी अत्याधुनिक चिप फैक्ट्रियां

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां) । भारत अब केवल मोबाइल और कंप्यूटर उपयोग करने वाला देश नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति

बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी चिप दिग्गज इंटेल और देश के प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा समूह ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस समझौते के तहत भारत में चिप्स की मैनुफैक्चरिंग, पैकेजिंग और असेम्बली की जाएगी, जिससे देश के उभरते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को नई मजबूती मिलेगी। टाटा समूह के अनुसार, इंटेल के उत्पादों की मैनुफैक्चरिंग गुजरात के धोलेरा में बन रही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में

होगी, जबकि उनकी पैकेजिंग और टेस्टिंग असम में स्थापित किए जा रहे टाटा के आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर एसेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट (ओएसएटी) में की जाएगी। इन दोनों अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए टाटा समूह लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यह निवेश भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। साझेदारी का एक बड़ा फोकस एआई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में

जिसकी वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया के टॉप-5 पीसी मार्केट्स में शामिल होगा। ऐसे में इस पहल से चर्चे बाजार में न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन को गति मिलेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। इंटेल एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे भारत के बढ़ते कंप्यूटिंग बाजार के लिए रणनीतिक फैसला बताया है। कहा कि एआई और पीसी की बढ़ती मांग भारत को एक महत्वपूर्ण टेक डेस्टिनेशन बना रही है।

न्यूज़ ब्रीफ

आईसीआईसीआई बैंक ने एएमएस में हिस्सेदारी बढ़ाई

नई दिल्ली । आईसीआईसीआई बैंक ने प्रूडेंशियल कारपोरेशन होल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड



(पीसीएचएल) से आईसीआईसीआई एएमसी में 2 फीसदी हिस्सेदारी 21.40 अरब में खरीदी। इस डील के बाद बैंक की हिस्सेदारी 51 से बढ़कर 53 फीसदी हो गई, जबकि पीसीएचएल की हिस्सेदारी 47 फीसदी रह जाएगी। आरबीआई ने इस सीदे को 12 सितंबर को मंजूरी दी। बैंक का यह कदम एएमसी में बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए उठाया गया है, खासकर स्टॉक-बेस्ड बोनस के कारण हिस्सेदारी में संभावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए। कंपनी अपना आईपीओ 12 दिसंबर 2025 को लॉन्च कर रही है। आईपीओ का आकार 10,600 करोड़ रुपए है और प्राइस बैंड 2,061-2,165 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस के तहत होगा, जिसमें सभी 4.89 करोड़ शेयर पीसीएचएल बेच रही है। इसका मतलब आईपीओ से जुटाई गई राशि कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि शेयर बेचने वाले प्रमोटर को प्राप्त होगी।

सरकार एकीकृत डिजिटल सीमा शुल्क प्लेटफॉर्म बनाएगी, 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म



नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2027 के बजट से पहले सरकार सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत मौजूदा तीन प्रमुख प्रणालियां आइसगेट, आरएमएस और आरसीईएस एकीकृत होकर राष्ट्रीय सीमा शुल्क प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगी। आइसगेट के जरिए व्यापारी ई-फाइलिंग और भुगतान करते हैं, आरएमएस जोखिम-आधारित जांच को स्वचालित करता है और आरसीईएस बैकएंड मूल्यांकन एवं वलीयर्स संभालता है। वर्तमान में ये तंत्र अलग-अलग काम करते हैं, जिससे कामगोी कार्रवाई और देरी होती है। नई परियोजना के लिए धन आवंटित कर सकती है। अभिरुचि पत्र जल्द जारी होने की संभावना है, जिसके बाद चयनित कंपनियों को तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव देने का मौका मिलेगा। परियोजना में स्टार्टअप्स को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। नई प्रणाली 1 अप्रैल 2027 से लागू होने का प्रस्ताव है और यह अप्रत्याश कर व्यवस्था में सबसे बड़ी आईटी परियोजना साबित होगी।

चावल कंपनियों के शेयर लड़खड़ाए, 10 फीसदी तक फिसले



मुंबई। भारतीय चावल कंपनियों के शेयर मंगलवार को बाजार खुलते ही तेज गिरावट के साथ खुले। केआरबीएल, एलटी फूड्स और जीआरएम ओवरसीज जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयर 3 से 10 फीसदी तक फिसल गए।

सोना 1,30,150 रुपए और चांदी लगभग 1,82,700 रुपए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती का रुख

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां) ।

घरेलू बाजार में मंगलवार को सोना और चांदी के वायदा भाव में मजबूती देखने को मिली।

कारोबारी साप्ताह की शुरुआत तेजी के साथ हुई,

जिससे निवेशकों के मनोबल में सुधार दिखाई दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स)

पर सोने का बेंचमार्क फरवरी कॉन्ट्रक्ट मंगलवार को 83 रुपये की बढ़त के साथ

1,30,045 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला,

जबकि पिछला बंद भाव 1,29,962 रुपये था।

इस समय सोने के वायदा भाव 166 रुपये

घटकर 1,30,128 रुपये पर पहुंच गए। दिन के

दौरान इसने 1,30,158 रुपये का उच्चतम और

1,30,042 रुपये का निचला स्तर छुआ।

इस साल सोने के वायदा ने 1,31,699 रुपये का उच्च स्तर दर्ज किया है। चांदी के वायदा भाव में भी मजबूत तेजी रही। एमसीएक्स पर मार्च कॉन्ट्रक्ट 1,027 रुपये की बढ़त के साथ 1,82,769 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 1,81,742 रुपये था। कारोबार के दौरान चांदी 954 रुपये उछलकर 1,82,696 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। दिन का उच्च स्तर 1,81,900 रुपये और निचला स्तर 1,80,974 रुपये रहा। इस वर्ष चांदी ने 1,84,743 रुपये प्रति किलोग्राम का सर्वोच्च स्तर छुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का माहौल देखने को मिला। कॉमेक्स पर सोना 4,219.60 डॉलर प्रति औंस पर खुला और इस समय 4,224.40 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो 6.70 डॉलर की मजबूती दर्शाता है। वहीं चांदी 58.51 डॉलर प्रति औंस पर खुलकर 58.95 डॉलर तक पहुंच गई। इसने इस वर्ष 59.61 डॉलर का उच्च स्तर दर्ज किया है। तेजी के मौजूदा दौर को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव आने वाले दिनों में कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।



महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सईवी 9ई पर ऑफर्स की घोषणा

नई दिल्ली । स्वदेशी कंपनी महिंद्रा ने अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी एक्सईवी 9ई पर आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की है। कंपनी की उक्त एसयूवी खरीद कर ग्राहक अधिकतम रुपए 3.80 लाख तक की बचत कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर बैरिपेट-आधारित होगा और इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस, कॉर्पोरेट बेंचिफिट्स, कम्प्लीमेंट्री पीपीएफ और एक्सटेंडेड वारंटी जैसे लाभ शामिल हैं। यह योजना दिसंबर 2025 तक वैध है और इसका उद्देश्य वर्ष के अंत में बिक्री को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी स्थिति और मजबूत करना है। महिंद्रा ने बताया कि यह फूट सिर्फ सामान्य प्राइस कटौती नहीं, बल्कि विभिन्न लाभों को मिलाकर बनाया गया एक बड़ा पैकेज है, जिसमें अलग-अलग बैरिपेट्स पर रुपए 1.55 लाख से रुपए 3.80 लाख तक का फायदा मिल सकता है। कंपनी का लक्ष्य ग्राहकों को लचीलापन देना है ताकि वे अपनी पसंद और बजट के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुन सकें। प्रीमियम फीचर्स के कारण एक्सईवी 9ई पहले से ही चर्चा में है। यह लगभग 4.8 मीटर लंबी कुल-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंज दिया गया है। एसयूवी दो बैटरी विकल्पों—59 कइब्ल्यूएच (542किमी रेंज) और 79कइब्ल्यूएच (656किमी रेंज) के साथ आती है। बड़ा बैटरी पैक मॉडल 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 6.8 सेकंड में पकड़ लेता है। दोनों ही बैरिपेट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, जो 20 मिनट में उपयोग योग्य रेंज चार्ज कर देता है।



बीज प्रमाणीकरण न कराया तो होगी वसूली: कृषि मंत्री



लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने 27 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को चेतावनी दी है, जिन्होंने अभी तक बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकरण नहीं कराया। मंत्री ने कहा कि यदि एफपीओ तुरंत पंजीकरण नहीं कराएंगे तो सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की वसूली की जाएगी। उन्होंने 32 एफपीओ के उत्पादित बीज के उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा अब तक न खरीदने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। कृषि निदेशालय में प्रदेश के 100 एफपीओ के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें 24 एफपीओ ने अब तक 80,960 क्विंटल बीज का उत्पादन और निगम को विक्रय किया। मंत्री ने कहा कि एफपीओ केवल गेहूं और धान ही नहीं, बल्कि दैचा के बीज भी प्रमाणित कर निगम को बेचेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, निदेशक कृषि, निदेशक बीज विकास निगम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इंडिगो की 4,500 उड़ानें रद्द होने से विमानन राजस्व प्रभावित

नुकसान की भरपाई के लिए विमानन कंपनी से मुआवजे पर किया जा रहा है विचार

नई दिल्ली, 09 दिसंबर (एजेंसियां) ।

पिछले सप्ताह इंडिगो ने लगभग 4,500

उड़ानें रद्द कीं, जिससे देश के प्रमुख निजी

हवाई अड्डा संचालकों का विमानन राजस्व

प्रभावित हुआ। वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न

छापने की शर्त पर बताया कि इस नुकसान की

भरपाई के लिए विमानन कंपनी से मुआवजे

पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा,

हमारी आपसी समझ और संवेदनशीलता को

ध्यान में रखते हुए संकट के स्थिर होने तक

अंतिम निर्णय टाला गया है। हवाई अड्डों का

बड़ा हिस्सा राजस्व विमानन गतिविधियों

से आता है, जिसमें लैंडिंग और

पार्किंग शुल्क शामिल हैं।

ये शुल्क विमानन कंपनियों द्वारा भुगतान किए

जाते हैं, लेकिन अक्सर टिकट की कीमतों में

शामिल कर यात्रियों पर आंशिक या पूर्ण रूप से



डाल दिया जाता है। हालांकि, गैर-विमानन राजस्व जैसे खुदरा बिक्री, इयूटी-फ्री, लार्ज सेवाएं और अन्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उनका योगदान अभी भी कुल राजस्व में विमानन के मुकाबले कम है। हवाई अड्डे सीधे यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क भी लेते हैं, जो सुरक्षा, सुविधा और अन्य सेवाओं में उपयोग होता है। कुछ हवाई अड्डों पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क भी लिया

जाता है, जिसका उपयोग हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरू और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डे इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सभी उड़ानें सामान्य होने के बाद ही नुकसान के आकलन और मुआवजे के निर्णय पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

3 ट्रिलियन...

उन्होंने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को एआई के साथ पनपने वाली कार्यबल को तैयार करने के लिए केंद्रीय बताते हुए कहा कि ब्लू कॉलर ही नया गोल्ड कॉलर है।आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वरी मुन्बराब ने तेलंगाना के पिछले एक दशक के परिवर्तन को उल्लेखनीय बताया, और कहा कि राज्य के आर्थिक लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लेकिन प्राप्त किए जा सकते हैं, बशर्ते वह विनिर्माण, कृषि, बुनियादी ढांचे और मानव विकास को मजबूत करे।फिल्म स्टार चिरंजीवी ने तेलंगाना को 3 ट्रिलियन लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और सरकार से फिल्म क्षेत्र में कौशल विकास को मजबूत करने का आग्रह किया।पूर्व यूके प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने एक वीडियो संदेश भेजा, जबकि प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम, अर्थशास्त्री कार्तिक मुल्लीधरन, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और एडोब सीईओ शांतनु नारायण ने वचुअल तरीके से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

10 प्रतिशत उड़ानें

बैठक में श्री एलबर्स ने बताया कि छह दिसंबर तक रद्द उड़ानों के लिए शत-प्रतिशत रिफंड जारी कर दिया गया है। मंत्री ने छह

दिसंबर के बाद की रद्द उड़ानों के लिए भी जल्द से जल्द रिफंड जारी करने और हवाई अड्डों पर अटक के सामान यात्रियों तक पहुंचाने की हिदायत दी।

उल्लेखनीय है कि दिसंबर में हजारों की संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विशेषकर पांच दिसंबर को इंडिगो की करीब 1,500 उड़ानें रद्द रही थीं। इंडिगो ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि उसने सोमवार और मंगलवार को 1,800 उड़ानों का परिचालन किया है जबकि बुधवार 10 दिसंबर को 1,900 उड़ानों के परिचालन की उसकी योजना है। इससे पहले श्री एलबर्स ने मंगलवार को एयरलाइंस का परिचालन सामान्य होने का दावा करते हुए यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अब एयरलाइंस की वेबसाइट पर जो भी उड़ानें दिख रही हैं, वे रद्द नहीं

सामाजिक योजनाओं ...

समिति ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों की समय पर सूची तैयार न करने से पीएम-दश योजना लगभग ठप हो गई। हालांकि मंत्रालय ने

बाद में 79.4 करोड़ रुपये जारी किए हैं, लेकिन समिति का कहना है कि 2025-26 के लिए प्रस्ताव पहले ही लेने चाहिए थे। समिति ने यह भी पूछा कि पीएम-दश को पीएमकेवीवाई में मिलाने से कहीं भविष्य के लाभार्थियों पर असर तो नहीं पड़ेगा।

माइक्रोसॉफ्ट करेगा 1.57 ...

जिसमें गूगल डेटा सेंटर की स्थापना भी शामिल है। कंपनी अगले पाँच वर्षों में देश में 1 करोड़ लोगों को एआई कौशल प्रशिक्षित करने में भी मदद करेगी। अपने माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के बेंगलुरु चरण में नडेला ने कहा कि भारत एक पीएम-दश नवाचार में तेजी से अग्रणी बन रहा है और देश भर में नए अवसर पैदा कर रहा है। आज हम बुनियादी ढाँचे और कौशल विकास में जिस निवेश की घोषणा कर रहे हैं, वह भारत को एआई-प्रमुख बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि देश भर के लोगों और संगठनों को व्यापक रूप से लाभ मिले।

व्यवस्था सुधारने के...

इसी दिशा में काम करेंगे।

श्री मोदी ने बैठक के बाद एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि संसद में राजग सांसदों के साथ हुयी बैठक में सुशासन को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य पर सकारात्मक चर्चा हुयी।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य अनावश्यक पेपरवर्क और लंबे फार्म की व्यवस्था को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नागरिकों को उनके द्वार पर सेवा मिले और उन्हें बार-बार अपना अपने कागज जमा न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की जिंदगी आसान बनाने के लिए तेज गति से सुधार कर रही है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुये उन्हें बिहार जीत का शिल्पकार बताया। श्री मोदी ने श्री कुमार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बनने को उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने नागरिकों पर भरोसा दिखाते हुए स्व प्रमाणन की सुविधा दी और यह व्यवस्था पिछले दस वर्षों से बिना किसी समस्या के काम कर रही है।

संसदीय दल की बैठक में बिहार में गठबंधन की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माला पहनाकर सांसदों ने स्वागत किया। यह बैठक संसद के पुस्तकालय भवन में आयोजित हुयी।



मीन – आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति कर्क का होकर चतुर्थ पारक्रम देशाटन राज्य भाव में चल रहा है। यह मनोरथ सिद्धि कारक है। धौलू स्तर पर भी मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि व निकट की यात्रा भी संभव है। रात्रि का कुछ समय परिवार के साथ बिताएं तो अच्छा रहेगा।



राजेश खन्ना से लेकर शशि कपूर तक: शर्मिला टैगोर ने सुपरस्टार्स के साथ जोड़ी बनाकर बॉलीवुड में पाया मुकाम



बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का नाम सुनते ही दर्शकों के दिमाग में हिट फिल्में, खूबसूरत मुस्कान और सुपरस्टार्स के साथ उनकी शानदार जोड़ी याद आती है। शर्मिला ने अपने करियर में सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपने आकर्षक अंदाज और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। राजेश खन्ना, धर्मेन्द्र, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ उनकी जोड़ी हमेशा लोगों की पसंदीदा रही। उनका यह अनोखा फैक्टर उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाने में मदद करता रहा और उन्हें बॉलीवुड की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को आंध्र प्रदेश के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। उन्होंने अपने सिने करियर की शुरुआत केवल 13 साल की उम्र में बंगाली फिल्म 'अपु

संसार' से की, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे ने बनाया था। इस फिल्म में शर्मिला ने छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी। बंगाली फिल्मों में लगभग पांच साल काम करने के बाद उन्हें बॉलीवुड में आने का अवसर मिला। उन्होंने 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म 'कश्मीर की कली' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई और उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर पहचान मिली। इसके बाद 1966 में आई फिल्म 'अनुपमा' ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शमार कर दिया। धर्मेन्द्र के साथ इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने बेहद सराहा और आलोचकों ने भी उनकी अभिनय प्रतिभा की तारीफ की। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी हमेशा लोगों के दिलों में

खास रही। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें और भी ज्यादा लोकप्रियता दिलाई। 'आराधना', 'अमर प्रेम', 'दाम' और 'छोटी बहू' में दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच हिट साबित हुई। राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी प्रभावशाली थी कि कई फिल्म क्रिटिक्स और दर्शक उन्हें बॉलीवुड की सबसे यादगार रोमांटिक जोड़ी मानते हैं। इसके अलावा, शर्मिला टैगोर ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ भी कई हिट फिल्में दीं। उनके साथ की गई फिल्मों में 'आ गले लग जा', 'वक्त' और 'अनाड़ी' शामिल हैं। फिल्मों में सुपरस्टार्स के साथ जो अद्भुत केमिस्ट्री देखने को मिली, वह दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।



शर्मिला ने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते। फिल्म 'आराधना' के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला। इसके बाद फिल्म 'मौसम' के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में बंगाली फिल्म 'अबर अरण्ये' में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए भी नेशनल अवॉर्ड मिला। शर्मिला टैगोर की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की और इस शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाया। इस शादी से उनके तीन बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा और सबा अली खान। उनकी शादी और पारिवारिक जीवन ने भी हमेशा मीडिया और दर्शकों का ध्यान खींचा।



जीवन में हर समय हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता : राधिका आप्टे

अभिनेत्री राधिका आप्टे हमेशा से अपने अलग अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। फिल्मों में अनोखे किरदार निभाने से लेकर निजी जीवन में अपने फैसलों पर कायम रहने तक, वह अक्सर ऐसी बातें कहती हैं जो उनके आत्मविश्वास और स्पष्टता को दर्शाती हैं। इस कड़ी में उन्होंने बताया कि वह करियर, शहर या मौके खोने जैसे दबावों को बहुत हल्के में लेती हैं।

राधिका आप्टे ने बताया कि उन्हें किसी भी चीज के छूट जाने का डर बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने कहा, "मैं इस तरह का दबाव कभी नहीं लेती। अगर मैं मुंबई में नहीं हूँ, तो मैं इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि मेरे हाथ से बड़े मौके निकल जाएंगे। फिलहाल मैं लंदन में रहती हूँ और काम के लिए भारत आती हूँ। कई लोगों का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र मुंबई होने के कारण, वहां स्थायी रूप से रहना जरूरी है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है।"

राधिका ने कहा, "अगर मुझे कोई काम पसंद आएगा या मैं उसे करना चाहूंगी, तो मैं खुद मुंबई आ जाऊंगी। और अगर कभी कोई प्रोजेक्ट छूट भी गया, तो भी यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में हर समय

हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कभी कुछ मिलता है, कभी नहीं, और दोनों ही स्थितियों को अपनाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "लंदन में रहने के बाद भी मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स हैं। इसलिए काम के पीछे भागने या लगातार उपलब्ध रहने का दबाव मैं खुद पर कभी नहीं लेती।"

उन्होंने कहा, "किसी भी चीज के छूट जाने का डर मेरे जीवन में ही नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बड़ा मौका चला जाएगा, तो जीवन पर असर पड़ेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम चीजों को जितना बड़ा समझते हैं, वे उतनी बड़ी होती नहीं। मानसिक शांति और जीवन के वास्तविक आनंद ही अहम हैं।"

राधिका आप्टे इन दिनों अपनी आने वाली थ्रिलर फिल्म 'साली मोहब्बत' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में वह एक ऐसी साधारण महिला स्मिता का किरदार निभा रही हैं, जो घर में रहना पसंद करती है। उसे बागवानी का शौक है और बेहद शांत जिंदगी जीती है। उसकी दुनिया छोटी-सी है।

लेकिन यही शांत दुनिया अचानक एक घटना के कारण बदल जाती है और कहानी एक रोमांचक दिशा में आगे बढ़ती है। यह फिल्म 12 दिसंबर को जी5 पर स्ट्रीम होगी।

फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ काम करने पर बोले शहजाद अली लगा, मैं तूफान के साथ तालमेल बैठा रहा हूं



फिल्मी दुनिया में जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा होती है, तो सिर्फ फिल्म से ही नहीं, उसके संगीत से भी उतनी ही उममीदें जुड़ जाती हैं। इन दिनों निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर ऐसा ही माहौल बना हुआ है। इस फिल्म के गाने 'इश्क जलाकर' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। इसमें गायक शहजाद अली और अभिनेता रणवीर सिंह की अनोखी केमिस्ट्री देखने और सुनने को मिलती है। शहजाद अली ने गाने में काम करने के अनुभव को साझा किया। 'इश्क जलाकर' को लेकर शहजाद ने कहा, "'धुरंधर' मेरे करियर का सबसे यादगार प्रोजेक्ट है। जब किसी कहानी में आग की तरह जोश और गहराई हो, तो संगीत बनाना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि व्यक्ति उस कहानी के भावों में पूरी तरह डूब जाता है। इस गाने में भी वही जुनून और वही जोश मौजूद है।"

शहजाद ने कहा, रणवीर सिंह के साथ काम करना इस प्रोजेक्ट की सबसे खास चीजों में से एक रहा। रणवीर ऐसे अभिनेता हैं जो हर सीन, हर इमोशन और हर संगीत को अपने अंदर उतार लेते हैं। वे गाने में शामिल नहीं होते, बल्कि उसे पूरी तरह जीते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी शैली और उनका जोशीला अंदाज कलाकारों को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, "रणवीर के साथ काम करते हुए ऐसा लगा मानो मैं एक तूफान या बिजली के झटके जैसी ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा रहा हूँ। यही वजह है कि मुझे 'इश्क जलाकर' गाने में भावनाओं का तूफान-सा महसूस होता है।"

शहजाद अली ने कहा, "'इश्क जलाकर' सिर्फ सुना जाने वाला ट्रैक नहीं है, बल्कि महसूस किया जाने वाला अनुभव है। यह गाना भावनाओं, संगीत और ऊर्जा के कारण लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह गाना जिस उत्साह के साथ मेरे पास आया था, मैंने इसमें उसी जुनून के साथ काम किया है।"

फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों की ओर से शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक आदित्य धर हैं, जो पहले ही 'आर्टिकल 370' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

फिल्म बॉर्डर-2 से अहान शेड्डी का दमदार लुक जारी, फिल्म जल्द होगी रिलीज

मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर-2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मेकर्स ने सखी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के बाद मंगलवार को अहान शेड्डी का पहला लुक रिवील कर दिया, जिसे देख फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अहान शेड्डी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला लुक शेयर किया, जिसमें अभिनेता खून से लथपथ पौजी की वर्दी पहने हुए जुनून के साथ चिल्लाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा, सरहद हो या समंदर, धरती मां का हर बेटा एक ही कसम निभाता है। 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज। पोस्ट शेयर करने के बाद दोस्त, परिवार और इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए। अहान शेड्डी के पिता और अभिनेता सुनील शेड्डी ने कमेंट करते हुए लिखा, सम्मान अपनी छाप छोड़ जाता है और हिम्मत तुम पर खूब जंचती है, बेटे। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने कमेंट सेक्शन में लिखा, वाह! अहान, कमाल कर रहे हो। इससे पहले मेकर्स ने सनी देओल, वरुण और दिलजीत का लुक शेयर किया था, जिसमें



उनके किरदार के नाम भी बताए गए थे। 'बॉर्डर-2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेड्डी के अलावा, मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का टीजर जारी किया जा चुका है। फिल्म 'बॉर्डर 2' के निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसका निर्माण गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले किया गया है। 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' का सीकल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित फिल्म थी।

हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप के साथ दिखे अभिनेता कार्तिक आर्यन, फोटो की शेयर



बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच उन्होंने हॉलीवुड के सुपरस्टार जॉनी डेप से मुलाकात की। बता दें कि कार्तिक आर्यन ने फिल्म 'भूल भुलैया 2' में 'रूह बाबा' और जॉनी डेप ने फिल्म पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन में समुद्री लुटेरे कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार निभाया था। फैंस और अभिनेता के दोस्तों को कार्तिक का ये अंदाजा काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिस्सूजा ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। जॉनी डेप हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, जिन्होंने 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' में कैप्टन जैक स्पैरो जैसे किरदार से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। दूसरी तरफ, कार्तिक आर्यन भी पिछले कई साल से बॉलीवुड में अपने अभिनय से

दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। 'प्यार का पंचनामा', 'सोनु के टीटू की स्वीटी', 'लुका छुपी' और 'भूल भुलैया 2' ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया है।

अभिनेता की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' है। समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा, फिल्म में नीना गुप्ता और जैकी शॉफ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म का निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा मिलकर कर रहे हैं। पहले यह फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

इसी के साथ ही क्रिसमस के मौके पर धर्मेन्द्र की आखिरी फिल्म इक्कीस भी रिलीज की जाएगी। अब देखना होगा कि दर्शक रोमांस और लव स्टोरी को पसंद करते हैं या देशभक्ति से भरी कहानी को सराहते हैं।

प्रिया गिल: फिल्म सिर्फ तुम ने रातोंरात बना दिया था सुपरस्टार, आज बसर कर रही गुमनाम जिंदगी



1999 में आई सुपरहिट फिल्म 'सिर्फ तुम' की वो मासूम अभिनेत्री तो आपको जरूर याद होगी, जिसने अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। हम यहां बात कर रहे हैं एक्ट्रेस प्रिया गिल की। 9 दिसंबर को बॉलीवुड की इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस का जन्मदिन है। इस अभिनेत्री ने फिल्म 'सिर्फ तुम' से ऐसी लोकप्रियता हासिल की कि उस जमाने की कई स्टार एक्ट्रेस काफी पीछे छूट गईं, लेकिन प्रिया गिल ने पिछले कई सालों से रूपहले पर्दे से दूरी बना रखी है। यहां तक कि वो सोशल मीडिया की दुनिया से भी दूर हैं। किंग खान और दबंग खान (शाहरुख और सलमान) के साथ काम कर चुकीं प्रिया गिल आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। रातोंरात करियर के शिखर पर पहुंचने वाली प्रिया को बॉलीवुड से इतनी मायूसी हाथ लगी कि उन्होंने इंडस्ट्री को ही अलविदा कह दिया। 1995 की मिस फाइनलिस्ट प्रिया गिल ने अपने करियर की शुरुआत अभिनेता चंद्रचूड़ के साथ 'तेरे मेरे सपने' फिल्म से की थी। फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद अभिनेत्री ऐसी एक फिल्म की तलाश में थी, जो उनके करियर का ग्राफ ऊपर ले जाती। उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई साल 1999 में आई फिल्म 'सिर्फ तुम' से।

इस फिल्म में उन्होंने संजय कपूर के साथ काम किया। इस फिल्म में उनकी खूबसूरती, एक्टिंग और मासूमियत ने दर्शकों का ध्यान खींचा और वह रातोंरात स्टार बन गईं। इसके बाद प्रिया गिल ने सलमान खान, शाहरुख खान और नागार्जुन के साथ काम किया। प्रिया गिल ने

'जोश' फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम किया। वह इस फिल्म में शाहरुख की हीरोइन बनी थीं। हालांकि, फिल्म में ऐश्वर्या राय भी थी, जो शाहरुख की बहन बनी थीं। इसके बाद 1999 में आई फिल्म 'बड़े दिलवाला' अभिनेत्री के करियर के लिए ग्रहण साबित हुई। इस फिल्म के बाद उनको केवल साइड रोल में देखा गया। हालांकि, इसके बाद अभिनेत्री 2003 में आई 'बॉर्डर हिंदुस्तान का' फिल्म में नजर आई थीं, लेकिन सफलता न मिलती देख एक्ट्रेस ने मलयालम फिल्मों का रुख किया और फिल्म मेघम में काम किया।

बाद में वह फिल्म 'पिया तोसे नैना लागे रे' में अखिलेश पांडे के अपोजिट दिखाई दी, लेकिन इसके बाद तो वह जैसे फिल्मों से गायब ही हो गईं। खास बात यह है कि प्रिया गिल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं। माना जा सकता है कि शायद उन्होंने शादी कर ली हो और दूर कहीं जिंदगी बसर कर रही हों।



शुभ लाभ

हरियाणा

बुधवार, 10 दिसंबर, 2025

बेंगलुरु

13

ड्राज का राशिफल

मेघ – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ

आज काफी सोच समझकर ही लोगों से बातचीत करनी चाहिए दिमाग को शांत ही रखना पड़ेगा। आपके जीवनसाथी से तनाव कारण बन सकता है. आप-अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा बाद में सम्बन्धों में गिरावट आ सकती है. किसी मित्र के सहयोग से आमदनी बढ़ सकती हैं धन की स्थिति में सुधार होगा. किसी अनुभवी की राय आपके लिए फायदेमंद रहेगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा ।

वृषभ – इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो

आज मन से दृढ़ होकर किसी भी काम को करेंगे वह अवश्य ही सफल होगा , परिणाम सार्थक और सकारात्मक होगा. जीवनसाथी के साथ थोड़ा समय बिताने, उसकी समस्याओं को ध्यान से सुनने और भा-वनाओं को बेहतर तरीके से समझने से संबंधों में मधुरता आएगी. आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव कम रहेगा , सामाजिक और राजनीति दोनों प्रकार का ही लाभ दिखेगा ।

मिथुन – क,कि,कृ,च,इ,छ,के,को,ह

आज आपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ धार्मिक यात्रा करली पड़ेगी । मा-ता-पिता की बातों को अन्देखा न करें । किसी काम को शुरू करने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लें, आपको फायदा जरूर होगा. अचानक धन लाभ का योग बन रहा है. आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी, जिसके साथ बात करके आपकी दिनभर की थकान दूर हो जायेगी. परिस्थितियां भी आपके अनुकूल रहेगी. आपको दूसरो की मदद करते रहना चाहिए मित्रों को निराश नही करना चाहिए ।

कर्क – ही,हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो

आज परिवार के सदस्यों से वाद विवाद हो सकता हैं जिससे मन दुखी होगा । पिछले कुछ समय से जिन गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे आज वह दूर हो सकते हैं. यात्रा कष्टदायी हो सकती है. अचानक सामने आने वाले कामों के लिए खुद को पहले से तैयार कर लें. जमीन संबंधी कोई लेन-देन कर रहे हैं, तो पहले अच्छे से उस जगह की जांच-पड़ताल कर लें. आज यात्रा कष्टदायक रहेगी जरूरी होंगे गुड का सेवन करके यात्रा का आरंभ करें।

सिंह – म,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे

आज बुद्धि का जबर्दस्त परिचय आप समाज के सामने देंगे आप की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रभावशाली वाणी होने के कारण लोगों से आप अपनी बात मनवा सकेंगे. इन कारणों से आप अपने व्यवसाय में अच्छा कर पाएंगे और प्रचुर लाभ कमा पाएंगे. यात्रा से भी लाभ मिलेगा. संतान या शिक्षा को लेकर यदि आप कोई प्रयास कर रहे थे, तो आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है. परन्तु जीवनसाथी या मित्रों के साथ बिना वजह विवाद हो सकता है. स्वास्थ्य एकदम तंदुरुस्त रहेगा।

कन्या – टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो

आज हनुमान मंत्रि मे गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर कार्य सिद्ध होंगे आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे.नजदीकी लोगों के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिले-गी.कार्यालय में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा. जो लोग सरकारी काम से जुड़े हैं, उनको कोई मंडिया आँडर मिल सकता है. घर में शुभ-प्रसंगों का आयोजन हो सकता है. जीवन में खुशियां बरकरार रहेगी. नंदी को मेहं का भूसा खिलाए।

तुला – र,री,रू,रे,रो,ता,ति,तू,ते

आज स्थान परिवर्तन का योग बनेगा आप स्थान परिवर्तन नही चाहते हैं तो भी मंगलवार को अनुमानजी को सिन्दूर चहाए , घर मे सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी परन्तु किसी को लेकर जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद होंगे. आत्मसम्मान मे कमी महसूस होगी . गाय को परिवार के साथ समय बितायेंगे. स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही है आज आप उससे राहत मिलेंगी. आज कोई नजदीकी या ग्रिय व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में मददगार होगा. मन उदास है तो शिव मंत्र का स्मरण करें।

वृश्चिक – तो,न,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू

आज का समय सफलताओं वाला हैं। परन्तु पारिवारिक मामलों से संबंधित झगड़ा हो सकता है. यदि आप उनसे दूर रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए समय प्रतिकूल है नई परियोजनाएं अमल में लाएंगी. व्यवसाय में उन लोगों को अपने उद्यमों में बढ़ावा मिलेगा और नई व्यापार केंद्र स्थापित करेंगे.बहुत बेचैनी हो तो किसी धार्मिक ग्रन्थों का आश्रय करें अथवा अपने ईश्वर का स्मरण करें।

धनु – ये,यो,भ,भी,भू,धा,फा,बा,भे

आज नक्षत्र बल आप को पूरा सहयोग देगा अपना व्यापार बढ़ाने के लिये आपको नये अवसर मिलेंगे. रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा उधार दिया हुआ पैसा अचानक ही वापस मिल जायेगा. कोई रिश्तेदार आपके घर पर अचानक से आ सकते हैं. इससे घर का वातावरण कुछ बदल सकता है. वच्चे काफी खुश नजर आयेंगे. बिजनेस के क्षेत्र में बड़े-बड़े लोगों से मिलने में मदद मिलेगी, आपकी तरक्की सुनिश्चित है. प्रातः मंत्रि के दर्शन करके दिन का शुभ आरंभ करना चाहिए रिश्ते मजबूत होंगे.शाम के वक्त परिवार के साथ दिनर का प्रोग्राम बनेगा।

मकर – भो,ज,जी,खि,खू,खे,खो,ग,गि

हनुमानजी को चमेली की पुष्प माला अर्पित करें जिससे पैसों का दबाव खत्म हो जाएगा. राहत मिल सकती है. पैसों के क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं. आज आप बड़ा फायदा दिलाने वाली डील कर सकते हैं. भूमि भवन आदि खरीदने के योग बन रहे हैं। आत्म-विश्वास बनाए रखें, आज आप किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे. रात्रि मे गहरी निद्रा के लिए हल्का सुपाच्छ भोजन करना होगा।

कुम्भ – गु,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

आप के विरोधी आप पर पैनी नजर बनाए हुए हैं अतः कार्य आरंभ से पूर्व अन्तिम क्षणों मे अपनी कार्य शैली को तुलन ही बखल ले आप के विरोधी पस्त हो जाएंगे । आज कुछ लोग बहुप्रतीक्षित सफलता प्राप्त करेंगे. आज आप वचनबद्धता से घिरे रह सकते हैं. किन्तु शुभ स्वास्थ्य हेतु तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें. आपको परिवार और व्यापार में संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है. इसके साथ समाज ही आप को सामाजिक गतिविधियों से सहयोगी बनना पड़ेगा।

मीन – टी,दू,थ,झ,ज,दे,दो,चा,ची

आज आप की पद प्रतिष्ठा में उन्नति हो सकती है. बिजनेस में अच्छी प्रगति के योग हैं. जीवनसाथी से भी मदद मिलती रहेगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी. पैसों से जुड़े किसी मामले को सुलझाने के लिहाज से आज का दिन अच्छा है. आपकी कुछ नए-पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है. आज आप को काम से फुर्सत मिल जाए तो परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बनना चाहिए।

आज का पंचांग

दिनांक : 10 दिसंबर 2025 , बुधवार

विक्रम संवत : 2082

मास : पौष , कृष्ण पक्ष

तिथि : षष्ठी दोपहर 01:48 तक

नक्षत्र : मघा रात्रि 02:45 तक

योग : वैधृति दोपहर 12:45 तक

करण : वणिज दोपहर 01:48 तक

चन्द्रराशि : सिंह

सूर्योदय : 06:35 , सूर्यास्त 05:42 (हैदराबाद)

सूर्योदय : 06:31 , सूर्यास्त 05:53 (बेंगलोर)

सूर्योदय : 06:24 , सूर्यास्त 05:45 (तिरुपति)

सूर्योदय : 06:25 , सूर्यास्त 05:35 (विजयवाड़ा)

शुभ चौघडिया

लाभ : 06:00 से 07:30

अमृत : 07:30 से 09:00

शुभ : 10:30 से 12:00

चल : 03:00 से 04:30

लाभ : 04:30 से 06:00

राहुकाल : दोपहर 12:00 से 01:30

दिशाशूल : उत्तर दिशा

उपाय : तिळी खाकर यात्रा का आरंभ करें

दिन विशेष : गण्डमूल रात्रि 02:45 तक , भद्रा दोपहर 01:48 से रात्रि 01:46 तक

श्री ऋषिदेव विषय में सप्पक करें ॐ

पं.चिदम्बर मिश्र (टिळू महाराज)

हमारे यहाँ पाण्डित्य पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा एवं मूल पाठ्यक्रम, वास्तुशान्ति, गृहप्रवेश,शतचंडी, विवाह, कुंडली मिलान, नवग्रह शान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी शंका समाधान किए जाते हैं फ़कड का मन्दिर, रिकार्डगंज, हैदराबाद, (तेलंगाना)

9246159232, 9866165126

chidamber011@gmail.com

अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बरखा जाएगा : भजनलाल

जयपुर, 09 दिसंबर (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र राज्य के विकास में महती भूमिका निभाता है। साथ ही, यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास की भी अहम कड़ी है। हमारी सरकार प्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। साथ ही, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक नवाचार एवं एआई का उपयोग करते हुए



नए खनिज ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों में खान क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि रोजगार को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे। उन्होंने

कहा कि खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा पुलिस, परिवहन एवं खान विभाग आपसी समन्वय कर अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन निर्धारण के लिए क्षेत्र में ड्रोन सर्वे को बढ़ाया जाए। साथ ही, खनन पट्टा क्षेत्रों एवं अवैध खनन स्थलों की जियो फैसिंग को और प्रभावी बनाया जाए। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में एम-सेण्ड के

उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एम-सेण्ड नीति 2024 जारी की गई है। इस नीति के माध्यम एम सैंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया है जिससे एम-सेण्ड के लिए प्रदेश में अनेक प्लांट्स संचालित हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन सभी प्लांट्स की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में खनिज संसाधनों की संभावनाओं को जानने के लिए भी प्रभावी कार्ययोजना बनाए जाने के भी

निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि खान विभाग द्वारा एम-सेण्ड पॉलिसी, मिनरल डवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और अवैध माइनिंग मॉनिटरिंग कमेटी का गठन, ई-रवन्ना, ई-टीपी के गलत इस्तेमाल के लिए टीम का गठन तथा अवैध खनन संवेदनशील क्षेत्रों में बाईंडर होम गार्ड की तैनाती जैसे कार्य किए गए हैं। साथ ही, प्रदेश में खनन से रॉयल्टी वृद्धि हेतु खनिज परिवहन के लिए जीप-एस एवं आरएफआईडी युक्त वाहनों की बाध्यता की जा रही है। समस्त विभागीय एमपैनल्ड वे-ब्रिज पर स्टेण्डर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग, तुलायंत्रों पर सेंसर्स, ए.आई. कैमरा सहित विभिन्न नवाचार किए गए हैं।इससे पहले प्रमुख शासन सचिव खान टी. रविकांत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खान एवं पेट्रोलियम विभाग के नवाचारों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मेड़ता में रामदेव नागला का भव्य स्वागत



मेड़ता (राजस्थानी, 09 दिसंबर (शुभ लाभ ब्यूरो)।

सिखवाल ब्राह्मण समाज के प्रमुख कार्यकर्ता, विभिन्न राजस्थानी संस्थाओं से जुड़े तथा अखिल भारतीय पुष्कर महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामदेव नागला के राजस्थान के मेड़ता-पुष्कर आगमन पर राष्ट्रीय महामंत्री एवं सिखवाल समाज मेड़ता के अध्यक्ष मच्छराज जी सिखवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान नागला का शाल ओढ़ाकर और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया।

नागला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर के नव-निर्माण एवं उसके कायाकल्प का कार्य पूर्ण

किया गया है। भवन के पिछले हिस्सों में नए निर्माण की तैयारियों के लिए अध्यक्ष तेजमलजी पांडिया, उपाध्यक्ष मच्छराज सिखवाल, निर्माण कार्य से जुड़े पदाधिकारीगणों, दानदाताओं एवं भामाशाहों का उन्होंने आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि समाजबंधुओं के लिए भवन में पूर्व की तरह सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। आज के इस सम्मान समारोह में मच्छराज पंडित, ओमप्रकाश पंडित, मुकेश पंडित, भैरूलाल व्यास, श्यामलाल व्यास, बुधराज तिवाड़ी फालकी, धनराज तिवारी एवं श्रीभगवान पंडित सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। अंत में नागला ने सभी का आभार प्रकट किया।

दिल्ली में 14 को 'वोट चोर-गद्दी छोड़' महारैली

जयपुर, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली में 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली में राजस्थान से कांग्रेसजनों की भागीदारी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल 10 दिसम्बर को सायं 05.00 बजे प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम जयपुर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक लगे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव भव जितेन्द्र सिंह, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित राजस्थान से एआईसीसी पदाधिकारीगण एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली को सफल बनाने हेतु की गई तैयारियों की तथा प्रदेशभर से रैली में भाग लेने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जाने वाले कांग्रेसजनों की सूची, वाहनों की संख्या रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं वाहन प्रभारी के फोन नम्बर सहित एआईसीसी संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल को सौंपेंगे।

राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के मुद्दे पर

सांसदों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ लोकसभाध्यक्ष से मिले दीपेन्द्र हुड्डा

चंडीगढ़, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सांसदों के एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और उन्हें परिवार की तरफ से दायर न्र्खत से भी अवगत कराया और कहा कि हरियाणा में खेल स्टेडियम की दुर्दशा के कारण उन्होंने 3 साल पहले अपने एमपी कोटे से साढ़े 18 लाख रुपये दिये, जो लगाये नहीं गये और अधिकारी फाइलें घुमाते रहे। जिसकी वजह से राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी

हार्दिक राठी को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्टेडियम की मरम्मत के लिए उनकी सांसद निधि से दिये गये साढ़े 18 लाख रुपये खर्च नहीं करने के पीछे अफसरों की आपराधिक लापरवाही है। दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि सदन के संरक्षक के रूप में स्पीकर इस मामले का सज़ान लें और आगे कार्रवाई करें। देश में एमपी कोटे के क्रियान्वयन के लिये नये दिशा-निर्देश और नियम बनाएं ताकि स्थानीय अफसरों की जिम्मेदारी तय हो सके। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में जय प्रकाश जेपी, सांसद वरुण मुलाना मौजूद रहे। सांसदों

के प्रतिनिधिमण्डल की मांग पर लोकसभाध्यक्ष ने तुरंत इस विषय का सज़ान लेते हुए एमपीलैड कमेटी के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को तलब किया और निर्देश दिया कि स्पीकर की अध्यक्षता में जल्द एक राष्ट्रीय बैठक बुलायी जाए, जिसमें देश भर के सांसदों को आमंत्रित किया जाए। उस बैठक के माध्यम से एमपीलैड के क्रियान्वयन के लिये नये दिशा-निर्देश व नियम बनाये जायेंगे ताकि देश में सांसद निधि के क्रियान्वयन में देरी के लिये जवाबदेही तय हो सके। स्पीकर ने एमपीलैड कमेटी के संयुक्त

ग्रामीण विकास से ही होगा देश का विकास : वन्दना आर्य

चूरू, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

जिला परिषद सभागार में मंगलवार को 'ग्राम स्वराज के 05 साल पुस्तिका' का विमोचन तथा जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं सरपंचाणों का अभिनन्दन समारोह जिला प्रमुख वन्दना आर्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रेता कोचर, उप जिला प्रमुख मेहेन्द्र नौल, प्रधान दीपचन्द राहड़, संजय कस्वा, मोहनी देवी, विनोद पूनियां, निर्मला राजपुरोहित, पंकज गुप्ता, ओम सारस्वत, फतेहचन्द सोती, दौलत तंवर, सुभाष जांगिड़, जिला परिषद सदस्य अनिता चौधरी, नौरंगलाल शिलू, राजकुमार सिहाण, मालीराम सारस्वत, ममता कंवर, कमला देवी, सुमन पूनियां, लोकराम, जगदीश प्रसाद, ममता सुण्डा, तिलोकाराम



कस्वां, सुमन देवी, विमला कालवा, श्योकरण जाट, गिरधारी परीक, दुर्गा मेघवाल, राकेश शर्मा, गोरीशंकर, नथुराम मेघवाल, आँकरामल प्रजापत आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वन्दना आर्य ने कहा कि ग्राम स्वराज भारत की लोकतांत्रिक परम्परा की आत्मा है। हमारे देश की विकास यात्रा ग्रामीण विकास से ही पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज प्रणाली के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, परन्तु इन चुनौतियों का सामना करते हुए अगर हम अपनी

भागीदारी निभाएं तो गांव का विकास होगा और गांव के विकास से देश विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, जल प्रबन्धन, उत्तम स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। चूरू विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि चूरू जिला परिषद ने ग्रामीण विकास को गति देने का काम किया है।

गुरुग्राम की दीक्षा विश्वकर्मा का 47वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए चयन

गुरुग्राम, 09 दिसंबर (एजेंसियां)।

47वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 14 से 18 दिसंबर 2025 तक नदिया जिला, पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएगी। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हरियाणा टीम 12 दिंसंबर को रवाना होगी। गुरुग्राम जिले के मैत्री इंटरनेशनल स्कूल की प्रतिभाशाली खिलाड़ी दीक्षा

कुमारी ने स्टेट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा टीम में जगह बनाकर जिले का गौरव बढ़ाया है। दीक्षा के चयन पर जिला सॉफ्टबॉल एसोसिएशन एवं स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। सभी ने आशा व्यक्त की है कि दीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा और गुरुग्राम का नाम रोशन करेंगी।

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 का स्थान लिया है। यह परिवर्तन न्याय प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हरियाणा में इन तीनों आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। ऐसे परिवर्तन के दौर में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।



बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का

यह विमोचन राजस्थान की ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हो रही है, जब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 ने

कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल अतिक्रमण हटाने के बाद बेघर परिवारों का हंगामा

सीएम नीतीश ने कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश

पटना/एजेंसियां।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण के हाजीपुर-महनार पथ से चकसिकंदर तक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघ-पुर तक की संपर्कता बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण करते रहे हैं और इसे जल्द पूरा करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुये कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। साथ-साथ



पहुंच पथ का भी निर्माण कार्य पूर्ण करें ताकि आवागमन निर्बाध और सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिये पटना पहुंचने में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु पर

भी यातायात का भार कम होगा तथा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सम्पर्कता के लिये लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा। इस पुल के निर्माण से पटना शहर के बाहर से ही लोग उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर आसानी के साथ आवागमन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमलोग राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगातार निर्माण कर आवागमन को सुगम बना रहे हैं। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा 23 जून 2025

को कच्ची दरगाह (पटना) से राघोपुर दियारा (वैशाली) तक नवनिर्मित पथांश का उद्घाटन किया गया था। पटना जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-30 पर अवस्थित कच्ची दरगाह एवं वैशाली जिला अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-103 पर अव-स्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर कुल 19.76 किमी लम्बाई के 6 लेन ग्रीन फिल्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 9.76 किमी लम्बा पुल तथा 10 किमी लम्बा पहुंच पथों का निर्माण कार्य होना है। इस

परियोजना की कुल लागत 4 हजार 988 करोड़ रुपये है। प्रथम चरण में कच्ची दरगाह, पटना से राघोपुर दियारा, वैशाली (कुल लम्बाई 4.57 किमी) का उद्घाटन हो चुका है। द्वितीय चरण में हाजीपुर-महनार पथ (एनएच-122बी) से चकसिकन्दर (एनएच-322) तक तथा तृतीय चरण में राघोपुर दियारा से हाजीपुर-महनार पथ (एचएच-122बी) का निर्माण किया जा रहा है। अब तक परियोजना की वर्तमान प्रगति 85 प्रतिशत है तथा शेष कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



समस्तीपुर/एजेंसियां।

हसनपुर प्रखंड के सैकड़ों बेघर हुए परिवार मंगलवार को समस्तीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम से न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं और पुरुषों की बड़ी संख्या अचानक कलेक्ट्रेट कैम्पस में पहुंची, जिससे सुरक्षा गाड़ों को उन्हें रोकने में काफी मशकत करनी पड़ी। बावजूद इसके, भीड़ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर धरने पर बैठ गई। इसी दौरान मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई व

न्याय का भरोसा दिया। दरअसल, 4 दिसंबर को हसनपुर थाना क्षेत्र के मंगलगढ़ कोठी की 13 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी। यह जमीन वर्ष 1993 से अतिक्रान्त थी। जमीन के प्रबंधक बिपीन कुमार सिंह द्वारा दायर वाद पर लंबी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस टीम पर पथराव भी किया। हालात तनाव-पूर्ण होने पर आगजनी भी हुई,

जिसमें एक महिला हीरा देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। प्रशासन ने दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया। जेसीबी की मदद से लगभग 280 झुग्गी-झोपड़ियां और खपरेल तथा एस्बेस्टस के बने घरों को हटाया गया, जिसके बाद प्रभावित परिवारों का आरोप है कि वे अब पूरी तरह बेघर हो गए हैं। पीड़ितों का कहना है कि वे कई दशक से वहां रह रहे थे और अब कड़ाके की ठंड में पत्नी टांगकर रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है।

तीन कॉन्ट्रैक्ट किलर तीन हथियारों के साथ गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर/एजेंसियां।

पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी हत्या की वारदात होने से बच गई। मामला गरहां ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने विशेष जांच अभियान के दौरान बाइक सवार तीन संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तीन अश्वेध हथियार, कई जिंदा कारतूस और मादक पदार्थ की एक खेप बरामद की गई है। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटियासा के पास कुछ युवक संदिग्ध हालात में घूम रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आरोपी भागने लगे, लेकिन पीछा कर तीनों को



गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गौव नखिल, रोहित कुमार और निखिल कुमार के रूप में हुई है। तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें रोहित पर पहले से मामला दर्ज है। एसडीपीओ टाउन 2 बिनीता सिन्हा की टीम द्वारा की गई सघन पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। पता चला कि यह गिरोह सुपारी किलर है और

मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र के एक प्रत्याशी की हत्या करने आया था। तीनों को यह काम साढ़े तीन लाख रुपये में सौंपा गया था। सिटी एसपी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले व्यक्ति की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें बड़े अपराधियों के लिंक मिलने की भी आशंका जताई है।

पटना/एजेंसियां।

पटना में बढ़ते ठंड को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। उनका यह आदेश आज से लागू है। अगले आदेश तक किसी भी विद्यालय का संचालन सुबह 8:00 बजे से पहले नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि गिरते तापमान को देखते हुए स्कूलों का समय बदला गया है। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है



कि सभी विद्यालय चाहे वह निजी हों या सरकारी सुबह 8 बजे से पहले किसी भी परिस्थिति में संचालित नहीं होंगे। विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और छात्रों व अभिभावकों को समय परिवर्तन की जानकारी समय पर उपलब्ध

शिकायतें भी बढ़ रही थीं। बस या ऑटो से सफर करने वाले बच्चों को कोहरे और ठंडी हवा से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में प्रशासन का यह कदम अभिभावकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। स्कूल संचालकों का भी मानना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय बिल्कुल उचित है। कुछ विद्यालयों ने अपने स्तर पर पहले ही समय में बदलाव कर दिया था। अब प्रशासनिक आदेश के बाद सभी स्कूलों में एकरूपता आ जाएगी। इसके साथ ही समय परिवर्तन के बाद शिक्षकों और

गैर-शिक्षण कर्मियों को भी अपने कार्यों का बेहतर प्रबंधन करने में सुविधा होगी। पिछले कुछ दिनों से पटना सहित पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है, जिसके कारण सुबह धुंध, कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। ऐसे मौसम में छोटे बच्चों का सुबह-सुबह स्कूल जाना चुनौतीपूर्ण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के समय में बदलाव कर छात्रों को ठंड से बचाने का प्रयास किया है।

भाजपा एमएलसी ने शराब पीने वालों के इलाज के लिए 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क आवंटन की मांग की

बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के दौरान शराब पीने पर चर्चा गरमा गई, जिसमें बीजेपी एमएलसी रविकुमार ने राज्य सरकार से शराब से होने वाली बीमारियों से पीड़ित शराबियों के इलाज के लिए अपने एक्साइज रेवेन्यू का एक हिस्सा रिजर्व रखने का आग्रह किया। नियम 330 के तहत यह मुद्दा उठाते हुए, रविकुमार ने कहा कि लगभग 3 प्रतिशत शराब पीने वाले पीलिया और लिवर खराब होने जैसी बीमारियों के कारण बीमार पड़ रहे हैं, और इलाज का



खर्च तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि शराब की बिक्री से राज्य के रेवेन्यू का 20 प्रतिशत ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए अलग से रखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई शराबी पीलिया और लिवर से जुड़ी दिक्कतों के कारण समय से पहले

मर रहे हैं। अगर सरकार उनके इलाज में मदद करती है, तो लोग ज्यादा शराब पिएंगे, और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। रविकुमार ने आगे कहा कि गारंटी योजनाओं को असल में नियमित शराब पीने वालों द्वारा फंड किया जा रहा है।

2 प्रतिशत से ज्यादा शराबी मर रहे हैं। पूरे देश में 1.5 लाख लोगों की जान चली गई है। हर पांच में से एक शराबी पीलिया से मर जाता है। शराबी सरकार की इनकम में काफी योगदान दे रहे हैं। इसका 20 प्रतिशत उनके इलाज के लिए आवंटित करें।

मंत्री आर बी तिम्मापुर ने लिखित जवाब में कहा कि शराब पीने वालों के मेडिकल इलाज के लिए अलग से फंड आवंटित करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्साइज विभाग से मिलने वाला रेवेन्यू पहले से ही स्वास्थ्य क्षेत्र में जाता है, और नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनाओं के तहत इलाज मिलता है। उन्होंने साफ किया फंड स्वास्थ्य विभाग की जरूरतों के हिसाब से आवंटित किया जाता है। मंत्री ने परिषद को यह भी बताया कि इस साल बीयर की बिक्री में काफी गिरावट आई है।

अप्रैल से सितंबर 2025 तक, 195 लाख केस बीयर बेची गई, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 47 लाख केस कम है, यानी 19.55 प्रतिशत की गिरावट। पूरे राज्य में भारी बारिश और ठंडे मौसम के कारण यह गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा किया गया रेवेन्यू विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहस में हिस्सा लेते हुए एमएलसी के शिवकुमार ने कहा कि मैसूरु और चामराजनगर के कुछ हिस्सों में, 25 साल की उम्र की महिलाएं भी शराब से होने

वाली मौतों के कारण विधवा हो रही हैं। उन्होंने कहा, युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। जब एस एम कृष्णा मुख्यमंत्री थे, तो आदिवासी इलाकों के 5 किमी के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज शराब घर-घर पहुंच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को शराब पीने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उनसे ज्यादा काम करवाया जा सके, और मांग की कि सरकार और शराब की दुकानें न खोले और हर जिले में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट नियुक्त करें।

मछली पकड़ने के बंदरगाहों पर मशीनीकरण, बर्थ के प्रबंधन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू: केंद्रीय मंत्री

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पुनर्वास, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण) मोड के तहत पुराने मंगलूरु बंदरगाह, मालपे बंदरगाह और कारवार बंदरगाह पर बर्थ के मशीनीकरण और प्रबंधन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने लोकसभा को बताया कि प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य सरकार ने होन्नावर बंदरगाह को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने कहा होन्नावर बंदरगाह परियोजना के लिए सभी आवश्यक तटीय विनियमन क्षेत्र और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। विकास कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में शुरू की गई अन्य पीपीपी आधारित बंदरगाह विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण) मॉडल पर सभी मौसम के लिए गहरे पानी वाले ग्रीनफील्ड बंदरगाह के विकास

के लिए जेएसडब्ल्यू केनी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना पर 4,118 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंत्री ने कहा सार्वजनिक सुनवाई पूरी हो गई है, पर्यावरण मंजूरी का इंतजार है। पविनाकुर्वे बंदरगाह का जिक्र करते हुए सोनोवाल ने कहा कि न्यू मंगलूरु पोर्ट अथॉरिटी (एनएमपीए) के सहयोग से इसे एक स्वतंत्र बंदरगाह के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव शुरू किया गया है। मानकी पोर्ट को विकसित करने के लिए आईआईटी, मद्रास द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। लेनदेन सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मालपे फिशिंग हार्बर के उन्नयन के लिए 12.50 करोड़ मंजूर किए हैं और काम वर्तमान में प्रगति पर है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मालपे मछली पकड़ने के बंदरगाह क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एक बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।



रखी चांदी, चांदी के जेवर, कुछ सोने के हल्के नाक फूल और गहने में रखा केश लूट लिया। घटना के

बाद सभी अपराधी फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक, करीब डेढ़ किलोग्राम चांदी की लूट की बात

दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले

वैशाली/एजेंसियां।

जिले के पातेपुर प्रखंड स्थित ईमादपुर मुंशी चौक पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच सोमवार को जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्प-ताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, ईमादपुर गांव में पिछले कई दिनों से दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को यह विवाद उस समय

हिंसक रूप ले लिया जब दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। आरोप है कि झड़प के दौरान दोनों ओर से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिससे गांव में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। एक पक्ष के चंद्रविजय राम का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2000 में संबंधित जमीन खरीदी थी, लेकिन दूसरे पक्ष के ईश्वर राम जबन उस पर खेती कर रहे हैं। वहीं, दूसरे पक्ष के भोला राम का कहना है कि वे अपने खेत में पानी दे रहे थे, तभी चंद्रविजय और उनके परिवार के लोग पहुंच गए।

चार बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान से चांदी-जेवरात उड़ाए

बेगूसराय/एजेंसियां।

बेगूसराय में सोमवार की शाम अपराधियों ने गन प्वाइंट पर बड़ी लूट को अंजाम दिया। मंसूरचक थाना क्षेत्र के गुरदासपुर चौक स्थित कामिनी ज्वेलर्स में लगभग 5 बजे दो बाइक पर सवार चार सशस्त्र बदमाश पहुंचे और दुकान में घुसते ही आधा शटर गिराकर मारपीट शुरू कर दी।

दुकानदार संजीत सोनी के अनुसार, बदमाशों ने दुकान में